



सीजेआई सूर्यकांत पर विवादित पोस्ट से घिरी कांग्रेस, माफी मांगी

तिरुवनंतपुरम । केरल में कांग्रेस की प्रदेश इकाई एक विवादित सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में है। पार्टी के आधिकारिक एक्स अकाउंट से भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत के इस्तीफे की मांग किए जाने के बाद केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) ने बिना शर्त माफी मांगी है। पार्टी ने कहा है कि न्यायपालिका के शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करना अनुचित था और इसे आधिकारिक मंच से नहीं किया जाना चाहिए था।

केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कानूनी नोटिस के जवाब में यह माफी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि विवादित पोस्ट पार्टी नेतृत्व की जानकारी या मंजूरी के बिना प्रकाशित की गई थी। उनके मुताबिक, पोस्ट के लिए जिम्मेदार विजय थोट्टाथिल को उनके पद से हटा दिया गया है। साथ ही, उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए भी कहा गया है। कांग्रेस की केरल इकाई ने विवादित बयान को वापस लेते हुए उससे खुद को अलग कर लिया है।

केरल कांग्रेस के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर 12 अक्तूबर को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को संबोधित करते हुए एक पोस्ट



साझा की गई थी। इसमें उनसे इस्तीफा देने की मांग की गई थी। पोस्ट में कहा गया था कि अगर कानून-व्यवस्था उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और उनकी जगह किसी ऐसे व्यक्ति को लाया जाएगा, जो इसे संभाल सके। इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर आलोचना हुई। विवाद बढ़ने पर पोस्ट को कुछ ही घंटों के भीतर हटा दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मनीष दुबे ने इस पोस्ट को लेकर कानूनी नोटिस जारी किया था। इसके जवाब में सनी जोसेफ ने कहा कि केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी संविधान, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और भारत के मुख्य न्यायाधीश के संवैधानिक पद का सम्मान करती है। उन्होंने साफ़ किया कि नोटिस में जिस बयान का जिक्र किया गया है, वह केपीसीसी या भारतीय राष्ट्रीय

कांग्रेस की आधिकारिक नीति नहीं है। पार्टी ने उन टिप्पणियों को अस्वीकार करते हुए वापस ले लिया है और मुख्य न्यायाधीश से बिना शर्त माफी मांगी है।

पोस्ट के पोछे कौन था और पार्टी ने क्या कार्रवाई की ? सनी जोसेफ के मुताबिक, विवादित पोस्ट विजय थोट्टाथिल ने पार्टी नेतृत्व की जानकारी और मंजूरी के बिना प्रकाशित की थी। इसके बाद उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। केपीसीसी ने उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का निर्देश भी दिया है। हालांकि, जोसेफ ने यह स्पष्ट किया कि उनकी ओर से मांगी गई माफी केवल केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से है। पार्टी ने इस मामले में अपनी आधिकारिक स्थिति स्पष्ट करते हुए विवादित पोस्ट से दूरी बना ली है।

विवादित पोस्ट मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में हुए प्रदर्शनों से जुड़े मामले की सुनवाई के बाद सामने आई थी। यह याचिका मतदाता सुचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर में कथित अनियमितताओं के आरोपों के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों से संबंधित थी।

कार्यकर्ता सक्रिय हैं, तो भाजपा है ताकतवर : नितिन

नई दिल्ली । भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने चिम्बेल में भाजपा गोवा की प्रदेश कार्यसमिति बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। नितिन नवीन ने कहा कि जब तक भाजपा का कार्यकर्ता उत्साह और ऊर्जा के साथ जमीन पर संघर्ष करेगा, तब तक कोई मोदी जी को हिला नहीं सकता। उन्होंने कहा कि आपका उत्साह और चेहरे का विश्वास मेरी ताकत को बढ़ा रहा है। मुझे आश्चर्य कर रहा है कि गोवा में 2027 में हर

बूथ पर कमल खिलेगा। गोवा की टीम ने तय कर लिया है कि इस बार सिर्फ सरकार नहीं बनानी है, बल्कि एक ऐसी सरकार बनानी है, जो प्रमोद जी के नेतृत्व में भाजपा द्वारा निरंतर बनाई गई विकास की गति को बरकरार रखते हुए विकसित गोवा का मार्ग प्रशस्त करे।

नितिन नवीन ने आगे कहा कि मैं आज गोवा के मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई देने आया हूं। पीएम मोदी की आत्मनिर्भर भारत का जो सपना देख रहे हैं, आप उस सपने



को गोवा के लिए भी सार्थक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। करीब 32,000 करोड़ रुपये का बजट इस राज्य का अपना हो गया है। जहां देश में कुछ ऐसे राज्य भी हैं, जो किसी भी दिन पार्टी के शीर्ष पद

कांन्टक में कांग्रेस की सरकार ने वादा पूरा नहीं किया। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने घोषणा पत्र के वादे पूरे नहीं किए। वहीं जहां-जहां हमारी सरकारें बनी हैं, हमने एक-एक संकल्प को सिद्धि की ओर पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि मैं आज भाजपा के उस वर्ग के साथ बैठा हूं, जिसने संगठन को गढ़ा है। गोवा में अगर आज हमारी सरकार है, तो आपकी मेहनत और परिश्रम के कारण है। भाजपा की खूबसूरती यही है कि अगर कोई कार्यकर्ता नीचे बैठा है, तो वह किसी भी दिन पार्टी के शीर्ष पद

पर बैठ सकता है, और यह सिर्फ भाजपा में हो सकता है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में लगातार विकास के नए आयाम जोड़े जा रहे हैं। सेवा और समर्पण के भाव से जिस प्रकार हमारी सरकारें काम कर रही हैं, उससे हम पूरी तरह आश्चर्य हैं कि हम 2027 और 2029 के मिशन को पूरा करेंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से राजनीति में कुछ ऐसे लोग भी सक्रिय हैं, जो राजनीति की परिभाषा को दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं।



मुख्यमंत्री ने प्रगतिशील किसानों को किया सम्मानित

रायपुर । किसानों की समृद्धि और उनकी आय बढ़ाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण जीवन का आधार खेती-किसानी है। अन्रदाता किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, खेती की लागत कम हो और सिंचाई सहित सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हों, इसके लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर के सिविल लाइंस स्थित सर्किट हाउस में श्रद्धेय मनहरण लाल पाण्डेय की जयंती के अवसर पर आयोजित ‘उत्कृष्ट कृषक रत्न सम्मान समारोह’ को संबोधित करते हुए यह बात कही।

डीएमके नेता ने स्कूलों से 400 करोड़ वसूले, मंत्री का आरोप

नई दिल्ली । तमिलनाडु के मंत्री निर्मल कुमार ने आरोप लगाया है कि डीएमके नेता और पूर्व स्कूली शिक्षा मंत्री अनबिल महेश पोय्यामोझी ने एक ही साल में स्कूलों से सर्टिफिकेट जारी करने के नाम पर पैसे वसूले और इस तरह पार्टी फंड के लिए 400 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम जमा की। निजी स्कूलों से जुड़े 100 करोड़ रुपये के रिश्त मामले में महेश की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए, टीवीके नेता निर्मल कुमार ने दावा किया कि स्कूल प्रबंधन को सर्टिफिकेट के लिए पैसे देने पर मजबूर किया गया और वसूली गई यह रकम पार्टी फंड में डाल दी गई। उन्होंने कहा कि हमने एक ऐसे मंत्री को गिरफ्तार किया है जिसने पार्टी फंड के नाम पर 400 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम वसूली है। यह ध्रुव के लिए बहुत शर्म की बात है। उन्होंने पैसे ऐंठने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने सर्टिफिकेट जारी करने के बदले पैसे मांगे और स्कूलों से यह रकम वसूली। अब, स्कूल खुद आगे आकर शिकायतें दर्ज करा रहे हैं।

हम जीत रहे हैं, चंद्रशेखर से गठबंधन खारिज: अखिलेश

लखनऊ । उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दल अपने प्रचार अभियान को तेज कर रहे हैं, जबकि गठबंधन और सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत जारी है। इस राजनीतिक सरगमी के बीच, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार (27 अक्टूबर) को चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के साथ गठबंधन की संभावना को खारिज कर दिया। साथ ही, उन्होंने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन औवैसी पर भी निशाना साधा। चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन की संभावना पर प्रतिक्रिया देते हुए, यादव ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि समाजवादी पार्टी उनके समर्थन के बिना भी जीत सकती है। उन्होंने कहा चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन क्यों होगा ? हम तो उनके बिना भी जीत रहे हैं। उन्होंने औवैसी का नाम लिए बिना उन पर भी निशाना साधा। उन्होंने पंतंग का उदाहरण देते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक खिलाड़ी पद के पीछे से मिलने वाले समर्थन के दम पर ही आगे बढ़ते हैं। यादव ने इशारा किया कि उनका राजनीतिक प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें पीछे से कितना समर्थन मिल रहा है।

अरुणाचल प्रदेश की सियांग नदी पर प्रस्तावित 11,200 मेगावाट की सियांग अपर मल्टीपर्पज परियोजना

भारत के लिए महत्वपूर्ण जलविद्युत परियोजना की रणनीतिक तैयारी

नीरज कुमार दुबे

अरुणाचल प्रदेश की सियांग नदी पर प्रस्तावित 11,200 मेगावाट की सियांग अपर मल्टीपर्पज परियोजना के विरोध में उठे स्वर्ण का लगातार तेज होना केंद्र और राज्य सरकार के लिए मुश्किलों का सबब बन गया है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र की ऊपरी धारा यारलुंग त्सांगपो पर चीन लगभग 60,000 मेगावाट क्षमता की विशाल जलविद्युत परियोजना बना रहा है। यह भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही नदी अरुणाचल प्रदेश में सियांग और आगे असम में ब्रह्मपुत्र कहलाती है। नदी के ऊपरी हिस्से पर चीन की बढ़ती क्षमता भारत के सामने जल प्रवाह, बाढ़ प्रबंधन और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े सवाल खड़े करती है।

वहीं भारत की प्रस्तावित सियांग परियोजना चीन की

बढ़ती जलविद्युत ताकत का जवाब देने की दिशा में एक अहम कदम है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के मुताबिक, इस परियोजना में करीब 9.2 अरब घन मीटर पानी जमा करने की क्षमता होगी, जबकि चीन की परियोजना की अनुमानित भंडारण क्षमता करीब 5.5 अरब घन मीटर है। यानी बिजली उत्पादन में चीन का बांध बड़ा हो सकता है, लेकिन पानी जमा करने के मामले में भारत की प्रस्तावित परियोजना अधिक सक्षम हो सकती है। यही इसकी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत है। अगर चीन भविष्य में ब्रह्मपुत्र के पानी के प्रवाह में बदलाव करता है, तो सियांग परियोजना भारत को जल प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प दे सकती है। इसलिए यह परियोजना केवल बिजली बनाने तक सीमित नहीं, बल्कि भारत की जल सुरक्षा मजबूत करने और चीन के मुकाबले अपनी रणनीतिक स्थिति बेहतर बनाने का भी अवसर है।



जहां तक इस परियोजना के विरोध की बात है तो आपको बता दें कि 23 अक्टूबर की रात पासीघाट में परियोजना विरोधी प्रदर्शन हिंसक हो गए। ह्हाइ कार्यालय और पुलिस थाने में आगजनी हुई तथा राजनीतिक प्रतिनिधियों के आवासों में तोड़फोड़ और लूटपाट की घटनाएं सामने आईं। पुलिसकर्मियों के घायल होने के बाद प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की और सार्वजनिक

जमावड़े पर प्रतिबंध लगाए। इस घटनाक्रम ने सरकार और स्थानीय संगठनों के बीच पहले से मौजूद अविश्वास को और उजागर किया।

रिपोर्टों के मुताबिक स्थानीय संगठनों ने यहां तक आरोप लगाया है कि केंद्र की परियोजना संबंधी पहल सियांग क्षेत्र को भारत-चीन रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का मैदान बना रही है। आदि बाने केबांग-यूनाइटेड नामक संगठन के प्रवक्ता दाितक रतन ने परियोजना के सर्वेक्षण, स्थानीय सहमति और पैतुक भूमि के अधिकारों को लेकर सवाल उठाए। संगठन ने दावा किया कि प्रभावित गांवों के लगभग 80 प्रतिशत परिवार परियोजना का विरोध कर रहे हैं। संगठन ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू को सार्वजनिक बहस की चुनौती भी दी और कहा कि वह विकास के खिलाफ नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों को अनदेखी करके विकास थोपे जाने के खिलाफ है।

देखा जाये तो इस विवाद का सबसे संवेदनशील पहलू स्थानीय लोगों की पहचान, सम्मान और सुरक्षा की भावना है। साथ ही आदि और गालो समुदायों के लिए सियांग नदी सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि उनकी कृषि, सांस्कृतिक पहचान, पारंपरिक जीवन और पूर्वजों की भूमि का आधार है। विरोधी संगठनों का दावा है कि प्रस्तावित जलाशय से 27 गांव डूब सकते हैं और लगभग डेढ़ लाख लोग विस्थापित हो सकते हैं। इसके अलावा, सीमावर्ती समुदाय भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के महत्वपूर्ण साझेदार हैं। यदि उन्हें लगता है कि उनकी जमीन, संस्कृति और भविष्य के बारे में निर्णय उनकी आवाज सुने बिना लिए जा रहे हैं, तो अविश्वास बढ़ सकता है। देखा जाये तो चीन के सामने भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए स्थानीय नागरिकों के साथ विश्वास का रिश्ता कमजोर करना किसी भी रणनीति के लिए नुकसानदेह होगा।

कलेक्टर ने अपर और डिप्टी कलेक्टरों के मध्य किया कार्य विभाजन

महासमुंद। जिले में प्रशासनिक कार्यों के सुचारू संचालन, विभागीय समन्वय तथा शासकीय कार्यों के प्रभावी निष्पादन के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री विनय कुमार लोहव ने अधिकारियों के मध्य पूर्व में सौंपे गए प्रभारों में संशोधन किया है। इसके तहत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर एवं डिप्टी कलेक्टरों के मध्य आगामी आदेश पर्यंत तक कार्य विभाजन करते हुए विभिन्न विभागों एवं जिला कार्यालय की शाखाओं की जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं। जारी आदेश के अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महासमुंद सुश्री



अनुपमा आनंद को जिला पंचायत के कार्यों के अतिरिक्त मुख्यमंत्री की घोषणाओं एवं निर्देशों, स्वास्थ्य, जिला आयुर्वेद, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, कृषि, पशु चिकित्सा सेवाएं, मत्स्य पालन, उद्यानिकी, रेशम, शिक्षा, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, क्रेडा, मुख्यमंत्री कौशल विकास, ग्रामोद्योग एवं हाथकरघा विभाग सहित विभिन्न विभागों का

प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। उन्हें कृषि विज्ञान केंद्र, नोडल जिला सहकारी बैंक, सीएसआर, निःशक्त कल्याण एवं पुनर्वास तथा जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों एवं समारोहों के लिए प्रभारी एवं समन्वयक की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।अपर कलेक्टर श्री सचिन भूतड़ा को अपर कलेक्टर सरायपाली का प्रभार सौंपते हुए बसना एवं सरायपाली तहसीलों के निर्धारित राजस्व प्रकरणों की प्रथम अपील, निगरानी एवं पुनरीक्षण प्रकरणों की सुनवाई तथा निराकरण की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अतिरिक्त संबंधित अनुविभागों में छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता

(संशोधन) अधिनियम, 2026 के अंतर्गत कलेक्टर की अधिकारिता में आने वाले द्वितीय अपील के प्रकरणों की सुनवाई एवं निराकरण का दायित्व भी सौंपा गया है। उन्हें नजूल पट्टों के नवीनीकरण तथा नजूल शाखा के निर्धारित प्रकरणों के अंतिम निराकरण की जिम्मेदारी भी दी गई है।

अपर कलेक्टर श्री रवि कुमार साहू को महासमुंद, बागबाहरा, कोमाखान एवं पिथौरा तहसीलों के निर्धारित राजस्व प्रकरणों की प्रथम अपील, निगरानी एवं पुनरीक्षण प्रकरणों की सुनवाई और निराकरण का दायित्व सौंपा गया है। इसके साथ ही संबंधित अनुविभागों के द्वितीय अपील

प्रकरणों, शोध क्षमता प्रमाण-पत्र जारी करने, अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी के कार्यों, जिला शहरी विकास अधिकरण, भू-अर्जन एवं भू-आवंटन तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं औषधि प्रशासन से संबंधित प्रकरणों के निराकरण की जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें भू-अभिलेख शाखा, जिला खनिज न्यास, जल जीवन मिशन, चिटफंड, लाइसेंस शाखा, एसडब्ल्यू शाखा एवं जेल निरीक्षण सहित विभिन्न शाखाओं तथा खाद्य विभाग, आदिवासी विकास, आवकरी विभाग, जिला परिवहन एवं नगरीय निकाय विभाग का प्रभारी अधिकारी भी बनाया गया है।

सड़क किनारे महिला ने दिया बच्चे को जन्म

पेट्रोलिंग टीम ने निभाई

अहम भूमिका, जानिए कहां

का है मामला

बालोद। बालोद जिले में मानवता की मिसाल देखने को मिली है, जहां सोनोग्राफी और नियमित जांच के लिए पति के साथ अस्पताल जा रही एक गर्भवती महिला को रास्ते में अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। इसके बाद पेट्रोलिंग टीम और स्वास्थ्य विभाग की तत्परता से सड़क किनारे महिला की डिलीवरी कराई गई। जच्चा-बच्चा दोनों सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार, गुरु थाना क्षेत्र के ग्राम टेंगनाबरपारा निवासी कुसुमलता सिन्हा अपने पति सतीश सिन्हा के साथ सोनोग्राफी और नियमित स्वास्थ्य



जांच कराने धमतरी जा रही थीं। इसी दौरान फागुनदहा चौक के पास उन्हें अचानक तेज प्रसव पीड़ा होने लगी। स्थिति को देखते हुए वह सड़क किनारे बैठ गईं। राहगीरों ने तत्काल इसकी सूचना हाईवे पेट्रोलिंग टीम को दी। सूचना मिलते ही आरक्षक मनोज मेश्राम, आरक्षक थमेंद्र देवांगन और वाहन चालक हीरेन्द्र साहू मौके पर पहुंचे। महिला की स्थिति को देखते हुए पेट्रोलिंग

टीम ने पुरुर शासकीय अस्पताल से स्वास्थ्यकर्मियों को अपने वाहन से घटनास्थल तक पहुंचाया। मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की सीएचओ माधवी धुरु, स्टाफ नर्स भारती साहू और वार्ड आया यशोमति साहू ने प्रसव कराने में अहम भूमिका निभाई। स्वास्थ्यकर्मियों की मदद से महिला ने सड़क किनारे ही एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया।

कहीं लाठी-डंडों से हमला तो कहीं आधी रात बदमाशों ने मचाया उत्पात

■ **टिकरापारा घटना को लेकर पुलिस ने पांच आरोपी गिरफ्तार**



धमतरी। शहर में लगातार सामने आ रही आपराधिक घटनाओं ने कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कहीं दुकानों के ताले टूट रहे हैं, तो कहीं आधी रात को बदमाशों के समूह गाली-गलौज करते हुए मोहल्लों में घूमते नजर आ रहे हैं। 21 अक्टूबर की रात धमतरी में एक ही रात तीन अलग-अलग वारदातें हुईं। 21 अक्टूबर को मुजगहन में चाकू और लाठी-डंडों से हुए हमले में दीपांशु साहू की जान चली गई, जबकि एक अन्य युवक घायल हुआ। इसी रात मराठापारा और बांसपारा इलाके में लाल गमछा बांधे युवकों का समूह कथित तौर पर लाठी-डंडों और हथियारों के साथ घूमता दिखाई दिया। गाली-गलौज और उत्पात की इन घटनाओं से इलाके में दहशत का माहौल बनने की बात सामने आई। इसी रात टिकरापारा में भी हथियारों और लाठी-डंडों से लैस युवकों के समूह की गतिविधियां सामने आईं। मामले में शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि, पुलिस के मुताबिक घटना में शामिल अन्य आरोपियों

बस्तर आईजी बट्री नारायण मीणा ने की मोर मितान कार्यक्रम की तारीफ

■ **बस्तर आईजी बट्री नारायण मीणा ने जिले की सुरक्षा का जायजा लिया.**

कांकेर। बस्तर आईजी बट्री नारायण मीणा दो दिनों के दौरे पर कांकेर पहुंचे। यहां उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की। पुलिस की कार्यप्रणाली, कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की स्थिति की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुलिस कार्यालय में अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कामकाज की जानकारी ली। पुलिस के मोर मितान कार्यक्रम की



उन्होंने सराहना की। आईजी बट्री नारायण मीणा ने अधिकारियों के साथ बैठक में कांकेर के लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की। उन्होंने गांवों में बीट प्रणाली को मजबूत करने और पुलिस की आम लोगों तक पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया, ताकि ग्रामीणों

की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान हो सके और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सके। उन्होंने कांकेर पुलिस द्वारा संचालित ‘मोर मितान’ कार्यक्रम को जनसंपर्क और जनसमस्याओं के निराकरण की

जताई कि पुलिस अधिकारी और कर्मचारी इसी तरह जिम्मेदारी के साथ जनसेवा करते हुए अपराधों की रोकथाम और आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए बेहतर कार्य करते रहेंगे।

बस्तर आईजी ने कहा कि पुलिस का दायित्व केवल अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना ही नहीं, बल्कि जनता के बीच विश्वास कायम करना, लोगों की समस्याओं को सुनना और उन्हें सुरक्षा का एहसास दिलाना भी है। उन्होंने जनसेवा, महिला-बाल सुरक्षा, साइबर जागरूकता और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की पहुंच मजबूत करने जैसे प्रयासों को महत्वपूर्ण बताया।

आरक्षक भर्ती की दूसरी सूची जारी करने की मांग तेज

कवर्धा में समथन में उतरी भीम आर्मी और गोंडवाना गणतंत्र ऑफ इंडिया पार्टी

कवर्धा। छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती-2023 की दूसरी सूची जारी करने की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। सोमवार को आंदोलनरत अभ्यर्थियों के समर्थन में भीम आर्मी और गोंडवाना गणतंत्र ऑफ इंडिया पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारी गृह मंत्री विजय शर्मा के कार्यालय का घेराव करने निकले, लेकिन पुलिस ने रास्ते में बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने सरकार और गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क पर



बैठकर विरोध जताया। अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में छूटे उम्मीदवारों को शामिल करने और करीब 1600 रिक्त पदों पर भर्ती की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि दूसरी सूची जारी करने को लेकर सरकार को स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए। इस मांग को लेकर चल रहे आंदोलन को अब विभिन्न संगठनों का समर्थन मिलने लगा है। भीम आर्मी समेत प्रदर्शनकारियों का कहना है कि

जब तक अभ्यर्थियों की चारों मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक संगठन उनके समर्थन में खड़ा रहेगा। मांगें पूरी नहीं होने पर मुख्यमंत्री निवास तक पैदल मार्च करने की चेतावनी भी दी।

प्रदर्शन के बाद भर्ती की दूसरी सूची जारी करने की मांग को लेकर आंदोलन और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। अब अभ्यर्थियों की नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी है।

बस्तर संभाग में साइबर ठगों ने उड़ाए दस करोड़, वापसी महज 19.62 लाख

जगदलपुर। बस्तर संभाग के सात जिलों में शातिर ठगों ने आम नागरिकों और सेवानिवृत्त कर्मियों की गाढ़ी कमाई पर डाका डालते हुए 10 करोड़ 61 लाख रुपये से अधिक की चपत लगा दी है। इसके विपरीत चिंताजनक पहलू यह है कि पुलिस अब तक महज 19.62 लाख रुपये की राशि ही वापस करा पाई है, जो कुल ठगी गई रकम का मात्र 1.85 प्रतिशत है। जन्वरी से सितंबर 2026 के आधिकारिक आंकड़े के अनुसार नौ महीनों के दौरान संभाग में कुल 117 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें से सिर्फ 38 मामलों में अदालत में चालान पेश किया जा सका।

सबसे दयनीय स्थिति बस्तर, कांकेर, कोंडगांव और सुकमा जिलों की रही, जहां पुलिस पीड़ितों का एक भी रुपया वापस कराने में नाकाम रही। बस्तर जिले में सर्वाधिक 44 मामले दर्ज हुए और 2.21 करोड़ रुपये लूटे गए, लेकिन रिकवरी शून्य रही।

वहीं बस्तर संभाग में सर्वाधिक 3.30 करोड़ रुपये की ठगी दंतेवाड़ा जिले में दर्ज की गई, जहां 20 मामलों में से 10 में चालान हुए और 7.58 लाख रुपये रिकवर किए गए। वहीं नारायणपुर में 14 मामलों में 5.21 लाख और बीजापुर में 9 मामलों में 6.82 लाख रुपये की रिकवरी हुई। बीजापुर में डिजिटल अरेस्ट का भी एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें एक पीड़ित को डरा-धमकाकर 2.01 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए गए।

साइबर अपराधों की जांच में आड़े आ रही बाधाओं पर विशेषज्ञों का कहना है कि ठग अंतरराष्ट्रीय गिरोहों के जरिए फर्जी सिम और म्युल बैंक खातों का इस्तेमाल करते हैं। पलक झपकते ही रकम कई खातों और ई-वॉलेट में ट्रांसफर कर ली जाती है। गोल्डन ऑवर में शिकायत न मिलने और दूसरे राज्यों की पुलिस से समन्वय में देरी के चलते रकम को फ्रीज कराना बेहद मुश्किल हो जाता है।

सामाजिक बहिष्कार पीड़ित परिवार ने डीएम से लगाई गुहार

धमतरी। जिले के कुरूद थाना क्षेत्र के ग्राम बोदाछापर का है। यहां नरोत्तम साहू और तीरथ राम साहू ने गांव के लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि परिवारों को डोनहा कहकर गांव से बहिष्कृत कर दिया है। पीड़ित परिवार ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि गांव में न तो इन परिवारों से कोई बात कर सकता है न ही इन्हें कोई रोजगार मिलता है। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग कुल 12 लोग इस सामाजिक बहिष्कार की मार झेल रहे हैं। परेशान होकर दोनों परिवार कलेक्टर कार्यालय पहुंच शिकायत दर्ज कराई। वहीं प्रशासन ने जांच के बाद कार्रवाई का आग्रह किया है। तीरथ राम साहू ने गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उनके नाती की मृत्यु के बाद परिवार ने शव को अपने बाड़ी में दफनाया था, जहां नाती की याद में मट बनाने की योजना थी, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने कब्र से शव निकालकर उसे रम्रथान ले जाकर जला दिया। जब उसने इसका विरोध किया तो गांव वालों ने उन्हें डोवहा कहकर 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।

नाका तोड़कर भागा ट्रक चालक,पुलिस ने दबोचा

बालोद। बालोद पुलिस ने एक ट्रक चालक को गिरफ्तार किया है, जिसने वन विभाग के अधिकारी के साथ अश्लिल गाली गलौज और मारपीट किया था। इसी के साथ ही पुलिस ने आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। यह पूरा मामला डौंडी नगर पंचायत के पास का है। बताया जा रहा है कि खनिज विभाग और वन विभाग के अधिकारी कांकेर जिले के कच्चे के वनोपज नाका में रात के दौरान ड्यूटी कर रहे थे और वाहन चेकिंग कर रहे थे। इस बीच रात लगभग 1 बजे ट्रक ड्राइवर अनियंत्रित तरीके से वाहन चलाते हुए नाका को पार कर फरार हो गया।इसके बाद वन कर्मचारियों ने उसका पीछा किया और डौंडी नगर पंचायत के पास उसे रोक लिया। गाड़ी के दस्तावेज मांगने पर ट्रक ड्राइवर ने कच्चे नाका के बैरियर प्रभारी घनश्याम तारम के साथ अश्लिल गाली गलौज और मारपीट किया। घटना के बाद वन विभाग के कर्मचारी ने इसकी शिकायत डौंडी थाने में किया। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ ही आगे की जांच शुरु कर दी।

महतारी वंदन योजना से साकार हो रहा दो सुकन्याओं का सुनहरा भविष्य

कांकेर। शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ ही उनके परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। महतारी वंदन योजना से लाभान्वित नरहरपुर आवासपारा वार्ड क्रमांक 11 की निवासी गायत्री नेताम इसकी एक प्रेरणादायक मिसाल है। उन्होंने योजना से मिलने वाली आर्थिक सहायता का सदुपयोग करते हुए अपनी दोनों बेटियों के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखी है। गायत्री नेताम बताती है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नाजिमा बेगम के सहयोग से उन्होंने महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन किया था। मार्च 2024 से उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिल रही है। यह राशि उनके लिए आर्थिक संवल साबित हो रही है और परिवार की जरूरतों को पूरा करने में मदद कर रही है। गायत्री ने इस सहायता राशि को केवल वर्तमान की जरूरतों तक सीमित न रखते हुए अपनी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने का माध्यम बनाया है।

कांकेर के बांसला में धान उपाजर्न केंद्र खोलने की मांग

कांकेर। जिले के ग्राम बांसला में स्थायी धान उपाजर्न केंद्र खोलने की मांग को लेकर किसानों ने जिला प्रशासन को जापन सौंपा है। किसानों का कहना है कि उपाजर्न केंद्र नहीं होने के कारण आसपास की तीन ग्राम पंचायतों के करीब एक हजार किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए 10 से 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। किसानों ने प्रशासन से धान खरीदी शुरू होने से पहले बांसला में स्थायी उपाजर्न केंद्र खोलने की मांग की है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से पहले किसानों ने अपनी मांग तेज कर दी है। कांकेर जिले के ग्राम बांसला में धान उपाजर्न केंद्र खोलने की मांग को लेकर किसानों ने एडीएम को जापन सौंपा। उनके मुताबिक पूर्व में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत यहां धान खरीदी केंद्र खोला गया था, लेकिन स्थायी केंद्र की मांग अब तक पूरी नहीं हुई है। ऐसे में किसानों को इस बार भी परेशानी होने की आशंका है। धान खरीदी का सीजन नजदीक होने के कारण किसान अब जल्द निर्णय लिए जाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि समय रहते बांसला में उपाजर्न केंद्र नहीं खोला गया।

पांच दिवसीय गायत्री पुस्तक मेला आज अंतिम

कोंडगांव। जिले में गायत्री परिवार द्वारा विचारों के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने और जन-जन तक जीवनोपयोगी साहित्य पहुंचाने के उद्देश्य से कोंडगांव में पांच दिवसीय विराट पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा। युग निर्माण योजना, मथुरा के तत्वावधान में विचारक्रांति अभियान के अंतर्गत आयोजित यह पुस्तक मेला आ अंतिम दिवस चलेगा। आयोजन को सफल बनाने के लिए जिला समन्वय समिति ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मेले के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न दायित्वों के निर्वहन के लिए 10 समितियों के गठन की प्रक्रिया जारी है। इस संबंध में चिखलपुटी आश्रम, कोंडगांव में जिला स्तरीय गोष्ठी आयोजित की गई। इसमें जिला समन्वय समिति कोंडगांव द्वारा सर्वसम्मति से मेले की व्यवस्थाओं को लेकर समितियों का गठन किया गया। आयोजन में जिले के पांच ब्लॉक कोंडगांव, बड़ेराजपुर, माकडी, केशकाल और फरसगांव की सहभागिता रहेगी।

बालोद की खूनी बहू को आजीवन कारावास

बालोद। जिले के डौंडीलोहारा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खड़ेनाडी में ससुर की बिजली करंट लगाकर हत्या करने के सनसनीखेज मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है।अपर सत्र न्यायालय बालोद ने ठोस वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मृतक की बहू और उसके प्रेमी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

घटना 16 जुलाई 2025 की रात की है। ग्राम खड़ेनाडी निवासी मनोहर निर्मलकर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी।अगली सुबह परिजन और बहू शव को अंतिम संस्कार



के लिए श्मशान घाट ले जाने की तैयारी कर रहे थे।इसी दौरान कुछ ग्रामीणों की नजर मृतक के चेहरे, गले और माथे पर मौजूद जलने और चोट के निशानों पर

पड़ी। ग्रामीणों को अनहोनी की आशंका हुई और उन्होंने तत्काल डौंडीलोहारा पुलिस को सूचना दे दी।मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में मौत की वजह बिजली का करंट लगना सामने आई। पुलिस विवेचना में सामने आया कि मनोहर निर्मलकर की हत्या उसकी बहू ने अपने

प्रेमी लेखाराम निषाद के साथ मिलकर की थी।आरोपी लेखराम हारमोनियम सिखाने वाला संगीत शिक्षक है। दोनों ने सोते समय

मनोहर को बिजली का तार लगाकर मार डाला था।वारदात पर पर्दा डालने के लिए आरोपियों ने ग्रामीणों को बताया कि मनोहर साइकिल से गिर गए थे, जिससे उन्हें चोटें आईं। करंट से त्वचा जलने के निशानों को छिपाने के लिए चेहरे और धावों पर हल्दी, गुलाल और तेल पोत दिया गया था।

डौंडीलोहारा पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (ब्रह्म) की धारा 103(1), 61(2) और 238 के तहत अपराध दर्ज किया।तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक मुकेश सिंह और साइबर सेल की टीम ने घटनास्थल का मुआयना कर

आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त बिजली का तार, रबर के दस्ताने, खून लगा गमछा और मोबाइल फोन बरामद किए।

कॉल डिटेल रिकॉर्ड और वैज्ञानिक साक्ष्यों के जरिए पुलिस ने अदालत के समक्ष मजबूत चालान पेश किया।अदालत में राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक घनश्याम सिंह साहू ने पैरवी की। न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को पुख्ता मानते हुए दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया।

छत्तीसगढ़ के जेलों में रिक्त पदों की भर्ती हेतु एचसी ने मांगा जवाब

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने डीजी

जेल से शपथपत्र में पूछा है कि जेलों में रिक्त पदों पर भर्ती कब तक की जाएगी। साथ ही बेमेतरा जिले के पथरॉ गांव स्थित ओपन जेल की सुरक्षा के लिए पुलिस बल कब तक उपलब्ध होगा, इस संबंध में भी डीजी जेल से शपथपत्र में जवाब मांगा है। पिछली बार हुई सुनवाई में राज्य सरकार ने शपथपत्र में बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश पर पथरॉ में ओपन जेल की स्थापना के लिए कदम उठाए गए हैं। 14 जुलाई 2026 के नोटिफिकेशन से जेल स्थापित की गई और 13 अगस्त 2026 को छत्तीसगढ़ ओपन जेल संचालन एवं प्रबंधन नियम, 2026 अधिसूचित किए गए। इनमें कैदियों की पात्रता, चयन और स्थानांतरण की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। सरकार ने जेल के संचालन के लिए 48 पदों के सृजन और



दिया गया है। कैदियों को कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए संबंधित संस्थानों के साथ समन्वय की पहल की गई है। ओपन जेल की बाहरी सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की एक कंपनी तैनात करने डीजीपी से कई बार अनुरोध किया गया है। नियम अधिसूचित होने के बाद पात्र कैदियों की पहचान और उनके स्थानांतरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। चीफ जस्टिस के आर महापात्र की डिलीजन बेंच ने सुनवाई के बाद कहा कि रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया बहुत ही धीमी है।

संक्षिप्त समाचार

मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण को लेकर राजनीतिक दलों के साथ बैठक आयोजित

रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग के



निर्देशानुसार अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 के संदर्भ में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गौरव सिंह की अध्यक्षता में कलेक्टर सभाकक्ष में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा प्राप्त प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रस्तावित युक्तियुक्तकरण की जानकारी दी गई तथा उनके सुझाव एवं विचार प्राप्त किए गए। बैठक में उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने प्रस्तुत प्रस्तावों पर अपनी सहमति व्यक्त की। उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया 02 नवंबर 2026 तक पूर्ण की जानी है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों की व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित एवं सुगम बनाना है।

रायपुर में द्वितीय चरण के जनसंख्या

गणना का प्रशिक्षण शुरू

रायपुर। भारत की जनगणना 2027 के द्वितीय



चरण के तहत रायपुर जिले में जनसंख्या गणना संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में द्वितीय चरण के अंतर्गत जनसंख्या गणना प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षण का उद्देश्य जनगणना कार्य से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक प्रक्रियाओं की जानकारी प्रदान करना तथा जनगणना कार्य के सुव्यवस्थित संचालन के लिए तैयार करना है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने जनगणना कार्य को अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दायित्व बताते हुए कहा कि जनगणना से प्राप्त आंकड़े देश एवं प्रदेश की विकास योजनाओं, नीतियों और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए जनगणना का प्रत्येक कार्य पूरी गंभीरता, जिम्मेदारी और सटीकता के साथ किया जाना आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए कि प्रशिक्षण के दौरान सभी प्रक्रियाओं को अच्छी तरह समझें तथा अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं सावधानी के साथ करें।

छ्तीसगढ़ में ईडी की रेड : रायपुर में

कारोबारी नितिन डंगा के घर दबिश



रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई को लेकर हलचल तेज हो गई है। रायपुर के साथ दुर्ग जिले में भी ईडी की टीम के दबिश देने की सूचना सामने आई है। दुर्ग शहर के गंजपारा इलाके में ईडी की रेड की खबर आई। प्राथमिक जानकारी के अनुसार भारतमाला से जुड़े मामले को लेकर छापेमारी चल रही है। जानकारी के मुताबिक, रायपुर के पंडरी स्थित रवि नगर के सुशील विला में कारोबारी नितिन डंगा के निवास पर ईडी की टीम पहुंची है। दुर्ग के ज़ख्म ग्रीन सिटी अपार्टमेंट में गुलशन बघेल रहते हैं। गुलशन के नाम पर बघेल कॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी भी संचालित है। इसके अलावा गुलशन बघेल ट्रांसपोर्टर भी हैं। रायपुर में हुई कार्रवाओं को भारतमाला परियोजना से जुड़े मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। इससे पहले भी इस मामले को लेकर कई जगह पर दबिश हुई थी। मंगलवार की सुबह 4 से 5 बजे के बीच रायपुर और दुर्ग में ईडी की छापेमारी की शुरु हुई है।

अर्नब साइक्लोन का असर, छत्तीसगढ़ में बदला मौसम

■ मौसम विभाग ने जारी किया रेड और ऑरेंज अलर्ट



भी बदल चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार के शाम से ही दक्षिण छत्तीसगढ़ में साइक्लोन अर्नब का असर आज शाम से ही देखने को मिल सकता है।

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर गायत्रीवाणी कांजीभोटला ने कहा आज की स्थिति में साइक्लोन अर्नब वेरी सीवियर साइक्लोन के रूप में विशाखापट्टनम कोस्ट से लगभग 300 किलोमीटर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में स्थित है।

■ कलेक्टर ने तैयारियों का लिया जायजा

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले राज्योत्सव 2026 को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में 2 नवंबर को नवा रायपुर अटल नगर स्थित सेंध लेक क्षेत्र में भारतीय वायु सेना के प्रसिद्ध सारंग हेलीकॉप्टर एयर शो का भव्य आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा और स्थल निरीक्षण के लिए रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह अधिकारियों के दल के साथ सेंध लेक पहुंचे।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कहा कि एयर शो में बड़ी संख्या में दर्शकों और अतिथियों के पहुंचने की संभावना है। ऐसे में दर्शकों की सुरक्षा, सुविधा और सुचारु यातायात प्रबंधन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आयोजन से संबंधित सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूर्ण कर



ली जाएं। स्थल निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने मुख्य मंच, वीआईपी सिटिंग एरिया और आम दर्शकों के बैठने के लिए सुव्यवस्थित प्रबंध करने के निर्देश दिए। उन्होंने वाहनों के सुचारु आवागमन के लिए प्रभावी ट्रैफिक प्लान बनाने, पर्याप्त पार्किंग स्थल चिन्हित करने, तथा प्रवेश और निकास मार्गों को सही ढंग से निर्धारित करने पर जोर दिया। इसके अलावा आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए आयोजन स्थल पर फर्स्ट एड किट, एम्बुलेंस

और मेडिकल टीमों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही कार्यक्रम में निर्बाध साउंड सिस्टम, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, स्वच्छ पेयजल, मोबाइल टॉयलेट और सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों को आपस में बेहतर समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए, जिससे एयर शो के दौरान आने वाले नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

महापौर मीनल के नेतृत्व में महिला स्वच्छता को बढ़ावा

जोन कार्यालयों को मिली सेनेटरी पैड वेंडिंग व इंसिनरेटर मशीनें

रायपुर। मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन, महिलाओं के स्वास्थ्य संरक्षण तथा सेनेटरी पैड की उपलब्धता एवं उनके स्वच्छ एवं वैज्ञानिक निस्तारण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज रायपुर नगर निगम द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई। स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने प्रमुख सुविधा प्रदाता (लीड फैसिलिटेटर) के रूप में निगम के विभिन्न जोन कार्यालयों हेतु सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन एवं इंसिनरेटर मशीनों का वितरण किया।

इन मशीनों की स्थापना से विशेष रूप से महिला सफाई मित्रों, महिला कर्मचारियों तथा जोन कार्यालयों में विभिन्न सेवाओं के लिए आने वाली



महिला नागरिकों को आवश्यकतानुसार सेनेटरी पैड की सहज उपलब्धता सुनिश्चित होगी। साथ ही उपयोग किए गए सेनेटरी पैड का वैज्ञानिक एवं सुरक्षित निस्तारण भी संभव हो सकेगा, जिससे स्वच्छता, स्वास्थ्य सुरक्षा और महिलाओं की गरिमा को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम में अपर आयुक्त विनोद कुमार पाण्डेय, कार्यपालन अभियंता एवं स्वच्छ भारत मिशन के नोडल अधिकारी योगेश कडू,

समस्त जोन स्वास्थ्य अधिकारी तथा निगम के अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने इस पहल को महिला स्वच्छता, स्वास्थ्य संरक्षण एवं जनहित की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। रायपुर नगर निगम, महिलाओं के लिए सुरक्षित, सुलभ और सम्मानजनक स्वच्छता सुविधाएँ उपलब्ध कराने तथा शहर को स्वच्छ, स्वस्थ और समावेशी बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

पत्थरों में जान डालने वाले मूर्तिकार की बेटी के सपनों को मिला नया आकार

रायपुर। पत्थरों को तराशकर खूबसूरत मूर्तियों का आकार देने वाले एक पिता की सबसे बड़ी खाहिश है कि उसकी बेटियां पढ़-लिखकर अपना भविष्य संवारे। अपनी कला से दूसरों की आस्था और कल्पनाओं को साकार करने वाला यह पिता अब अपनी बेटियों के सपनों को भी नई उड़ान देना चाहता है। धमतरी जिले के ग्राम लोहरसी निवासी मूर्तिकार श्री मनोज कुमार गंगंबर की इसी उम्मीद को छत्तीसगढ़ शासन की मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना ने नया संबल दिया है। योजना के तहत उनकी बेटी ऐश्वर्या को 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलने से परिवार में खुशी और आत्मविश्वास का नया संचार हुआ है।

मनोज कुमार गंगंबर अपनी मेहनत और कलात्मक हुनर से पत्थरों को आकर्षक मूर्तियों में ढालते हैं। मूर्तिकारी ही उनके परिवार की आजीविका का प्रमुख साधन है। काम के ऑर्डर के अनुसार होने वाला आमदनी से घर की जरूरतें पूरी करने के साथ दो बेटियों की शिक्षा का खर्च उठाना उनके लिए आसान नहीं था। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने बेटियों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने



इसी दौरान श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक श्री गंगंबर को मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना की जानकारी मिली। उन्होंने बेटी ऐश्वर्या के लिए आवेदन किया। आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन और पात्रता संबंधी प्रक्रिया पूरी होने के बाद योजना के अंतर्गत 20 हजार रुपये की सहायता राशि सभी ऐश्वर्या के बैंक खाते में अंतरित की गई।

बेटी के खाते में सहायता राशि पहुंचने से परिवार की आर्थिक चिंता कुछ कम हुई है। इस राशि से ऐश्वर्या की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। श्री गंगंबर के लिए यह सहयोग इसलिए भी विशेष है, क्योंकि अब वे अपनी आजीविका के साथ बेटी की पढ़ाई को लेकर अधिक आश्वस्त हैं। जिस पिता के हाथ पत्थरों को सुंदर आकार देते हैं, उन्हीं हाथों की मेहनत से संजोए गए बेटी के सपनों को अब शासन की योजना का सहारा मिला है।

देने का संकल्प लिया। उनकी इच्छा थी कि बेटियां अच्छी शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनें और जीवन में आगे बढ़ें।

छत्तीसगढ़ के विकास का प्रमुख इंजन बनेगा हाउसिंग बोर्ड, आवास के साथ अधोसंरचना विकास में निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका : चौधरी

रायपुर। वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल आने वाले वर्षों में प्रदेश के आर्थिक और अधोसंरचनात्मक विकास का प्रमुख इंजन बनेगा। हाउसिंग बोर्ड को केवल आवास निर्माण तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि सड़क, पुल, खेल अधोसंरचना, सार्वजनिक भवनों, टाउन प्लानिंग और शहरी पुनर्विकास जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में भी इसकी भागीदारी बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के लक्ष्य को साकार करने के लिए मंडल को परंपरागत कार्यप्रणाली से आगे बढ़कर नवाचार, आधुनिक तकनीक, वित्तीय प्रबंधन और परिणामोन्मुखी कार्यसंस्कृति अपनानी होगी।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री चौधरी मंगलवार को नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद के ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय तकनीकी प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला का उद्देश्य मंडल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तकनीकी दक्षता, प्रशासनिक क्षमता, वित्तीय प्रबंधन और कार्यकुशलता में वृद्धि करना तथा उन्हें आधुनिक निर्माण



तकनीकों, नवाचारी वित्तीय मॉडल और अधोसंरचना विकास की नई संभावनाओं से परिचित कराना था। मंत्री चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल को आर्थिक रूप से सुदृढ़, आत्मनिर्भर और बहुआयामी अधोसंरचना विकास संस्था के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से मंडल की वित्तीय स्थिति में सुधार, रिक्त संपत्तियों के विक्रय, नई परियोजनाओं के चयन और कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार किए जा रहे हैं।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि कुछ वर्ष पूर्व हाउसिंग बोर्ड गंभीर वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहा था। बड़ी ऋण देनदारी, सीमित परियोजनाओं और लंबे संपत्तियों के कारण

संस्था की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई थी। उन्होंने कहा कि हाउसिंग बोर्ड बजट आधारित संस्था नहीं है। उसे अपनी परियोजनाओं, सेवाओं और संसाधनों के माध्यम से आय अर्जित कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना होगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने वित्त विभाग के सहयोग से लगभग 700 करोड़ रुपये की लंबित ऋण देनदारी समाप्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इससे मंडल को बड़े वित्तीय दबाव से राहत मिली और नई परियोजनाओं की दिशा में आगे बढ़ने का अस्सर प्राप्त हुआ।

श्री चौधरी ने कहा कि लंबे समय से रिक्त पड़ी संपत्तियों के विक्रय के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना लागू की गई। आकर्षक छूट, प्रभाव्य विपणन और निरंतर निगरानी के माध्यम से बड़ी संख्या में संपत्तियों का विक्रय संभव हुआ। इससे मंडल की वित्तीय स्थिति में सुधार के साथ उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग की भी बढ़ावा मिला। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए मंडल अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव सहित अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना की।

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 में हवाई करतब दिखावे रायपुर पहुँची सारंग हेलीकॉप्टर प्रदर्शन टीम

रायपुर। भारतीय वायु सेना की सारंग हेलीकॉप्टर प्रदर्शन टीम छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित तीन दिवसीय राज्योत्सव 2026 में भाग लेने के लिए आज रायपुर पहुँची। टीम नवा रायपुर अटल नगर स्थित सेंध झील क्षेत्र के ऊपर शानदार हवाई प्रदर्शन से दर्शकों को रोमांचित करेगी।

स्वदेश में विकसित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (एएलएच) ध्रुव से उड़ान भरने वाली सारंग टीम अपनी सटीक उड़ान, समन्वित संरचनाओं और रोमांचक हवाई करतबों के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रदर्शन भारतीय वायु सेना के उत्कृष्ट उड़ान कौशल, अनुशासन, टीम भावना और पेशेवर दक्षता के साथ भारत की स्वदेशी हेलीकॉप्टर क्षमताओं को भी प्रदर्शित करेगा। यह आयोजन नागरिकों, विद्यार्थियों, युवाओं और विमानन में रुचि रखने वालों को हेलीकॉप्टरों की सामूहिक उड़ान में सटीकता और आपसी तालमेल देखने का अवसर प्रदान करेगा।



राज्योत्सव में सारंग की भागीदारी समारोह के आकर्षण को बढ़ाने के साथ भारतीय वायु सेना और छत्तीसगढ़ के नागरिकों के बीच जुड़ाव को और सुदृढ़ करेगी।

मोर से प्रेरित अपनी विशिष्ट रंग-सज्जा और आदर्श वाक्य उत्कृष्टता से प्रेरणा के साथ सारंग हेलीकॉप्टर प्रदर्शन टीम राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भारतीय वायु सेना की उत्कृष्टता का प्रतिनिधित्व करती है। रायपुर में टीम की उपस्थिति युवाओं को प्रेरित करने तथा उनमें विमानन और राष्ट्रसेवा के प्रति रुचि जगाने का माध्यम बनेगी।

अपूर्ण एवं अपंजीकृत परियोजना पर सीजी-रेरा की कार्रवाई

वात्सल्य गौरव-1 के प्रमोटर को आर्बटी को 6.87 लाख ब्याज भुगतान करने का आदेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (सीजी-रेरा) ने भू-संपदा परियोजनाओं में आर्बटियों के हितों की सुरक्षा और रेरा अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। प्राधिकरण ने रायपुर जिले के सेजबहार स्थित वात्सल्य गौरव-1, फेज-1 परियोजना के विकास कार्य अपूर्ण रहने तथा पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए जाने के मामले में प्रमोटर को आर्बटी के पक्ष में 6 लाख 87 हजार 496 रुपये ब्याज राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने तक प्रतिमाह 7 हजार 314 रुपये ब्याज भुगतान करने का भी आदेश दिया गया है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण की सुनवाई के दौरान पाया गया कि संबंधित परियोजना में स्वीकृत ले-आउट के अनुरूप विकास कार्य पूर्ण नहीं किए गए हैं। साथ ही सक्षम प्राधिकारी से परियोजना का पूर्णता प्रमाण पत्र भी प्राप्त नहीं किया गया है। इन तथ्यों के आधार पर प्राधिकरण ने परियोजना को अपूर्ण एवं चालू परियोजना की श्रेणी में मानते



हुए भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 18 के अंतर्गत विलंब के लिए ब्याज भुगतान का आदेश पारित किया है।

प्राधिकरण के आदेश के अनुसार, प्रमोटर को आर्बटी द्वारा भुगतान की गई 8 लाख 12 हजार 643 रुपये की राशि पर वर्ष 2019 से अक्टूबर 2026 तक 10.80 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के आधार पर कुल 6 लाख 87 हजार 496 रुपये का भुगतान करना होगा। इसके साथ ही 1 नवंबर 2026 से परियोजना का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने तक आर्बटी को प्रतिमाह 7 हजार 314 रुपये की राशि का भुगतान करना होगा।

प्राधिकरण ने परियोजना का रेरा पंजीयन नहीं कराए जाने के मामले को

भी गंभीरता से लिया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि भू-संपदा अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत पात्र परियोजनाओं का पंजीयन अनिवार्य है। इसके बावजूद संबंधित परियोजना का पंजीयन नहीं कराए जाने पर प्रमोटर के विरुद्ध अधिनियम की धारा 59 के अंतर्गत पृथक प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। प्राधिकरण के इस आदेश से स्पष्ट है कि किसी परियोजना में भूखंडों का विक्रय कर देने मात्र से प्रमोटर की वैधानिक जिम्मेदारियां समाप्त नहीं हो जाती हैं। स्वीकृत ले-आउट के अनुरूप सड़क, नाली, विद्युत, पेयजल सहित निर्धारित विकास कार्यों और आवश्यक आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करना प्रमोटर का दायित्व है। सीजी-रेरा द्वारा पारित यह आदेश भू-संपदा क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्बटियों के अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण है। इससे यह संदेश भी मिलाता है कि परियोजनाओं के विकास में अनावश्यक विलंब तथा रेरा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले प्रमोटरों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार रायपुर

तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.)

// ईश्वरहार //
रा.प.क्र./अ-6/वर्ष 2026-2027
रायपुर, दिनांक 23/10/2026गाम कांडुल, प.ह.नं. 83
रा.प.क्र./अ-6/वर्ष 2026-2027
रायपुर, दिनांक 23/10/2026गाम कांडुल, प.ह.नं. 83
रा.प.क्र./अ-6/वर्ष 2026-2027
रायपुर, दिनांक 23/10/2026गाम कांडुल, प.ह.नं. 83
रा.प.क्र./अ-6/वर्ष 2026-2027
रायपुर, दिनांक 23/10/2026गाम कांडुल, प.ह.नं. 83
रा.प.क्र./अ-6/वर्ष 2026-2027
रायपुर, दिनांक 23/10/2026गाम कांडुल, प.ह.नं. 83
रा.प.क्र./अ-6/वर्ष 2026-2027
रायपुर, दिनांक 23/10/2026गाम कांडुल, प.ह.नं. 83
रा.प.क्र./अ-6/वर्ष 2026-2027
रायपुर, दिनांक 23/10/2026गाम कांडुल, प.ह.नं. 83
रा.प.क्र./अ-6/वर्ष 2026-2027
रायपुर, दिनांक 23/10/2026गाम कांडुल, प.ह.नं. 83
रा.प.क्र./अ-6/वर्ष 2026-2027
रायपुर, दिनांक 23/10/2026गाम कांडुल, प.ह.नं. 83
रा.प.क्र./अ-6/वर्ष 2026-2027
रायपुर, दिनांक 23/10/2026गाम कांडुल, प.ह.नं. 83
रा.प.क्र./अ-6/वर्ष 2026-2027
रायपुर, दिनांक 23/10/2026

न्यायालय अति. तहसीलदार रायपुर,

जिला रायपुर (छ.ग.)

// ईश्वरहार //
रा.प.क्र./अ-6/वर्ष 2026-2027
रायपुर, दिनांक 23/10/2026गाम कांडुल, प.ह.नं. 83
रा.प.क्र./अ-6/वर्ष 2026-2027
रायपुर, दिनांक 23/10/2026गाम कांडुल, प.ह.नं. 83
रा.प.क्र./अ-6/वर्ष 2026-2027
रायपुर, दिनांक 23/10/2026गाम कांडुल, प.ह.नं. 83
रा.प.क्र./अ-6/वर्ष 2026-2027
रायपुर, दिनांक 23/10/2026गाम कांडुल, प.ह.नं. 83
रा.प.क्र./अ-6/वर्ष 2026-2027
रायपुर, दिनांक 23/10/2026गाम कांडुल, प.ह.नं. 83
रा.प.क्र./अ-6/वर्ष 2026-2027
रायपुर, दिनांक 23/10/2026गाम कांडुल, प.ह.नं. 83
रा.प.क्र./अ-6/वर्ष 2026-2027
रायपुर, दिनांक 23/10/2026गाम कांडुल, प.ह.नं. 83
रा.प.क्र./अ-6/वर्ष 2026-2027
रायपुर, दिनांक 23/10/2026गाम कांडुल, प.ह.नं. 83
रा.प.क्र./अ-6/वर्ष 2026-2027
रायपुर, दिनांक 23/10/2026गाम कांडुल, प.ह.नं. 83
रा.प.क्र./अ-6/वर्ष 2026-2027
रायपुर, दिनांक 23/10/2026गाम कांडुल, प.ह.नं. 83
रा.प.क्र./अ-6/वर्ष 2026-2027
रायपुर, दिनांक 23/10/2026

पेट्रोल के वैश्विक संकट के बीच भारत का मास्टरस्ट्रोक!

किशन सनमुखदास भावनारी

वैश्विक स्तरपर भारत की ऊर्जा सुरक्षा के इतिहास में 26 अक्टूबर 2026 एक महत्वपूर्ण तारीख़ के रूप में सामने आया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन करके 100 प्रतिशत तक एथेनॉल वाले ई100 ईंधन पर चलने वाले वाहनों के लिए नियामकीय रास्ता साफ़ कर दिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना में ई100 को ई 85 के साथ वाहन उत्सर्जन और परीक्षण संबंधी नियमों में शामिल किया गया है। इसका अर्थ है कि वाहन निर्माता अब निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुसार ई100 और अन्य उच्च एथेनॉल मिश्रणों पर चलने वाले फ्लेक्स-प्यूल वाहनों का परीक्षण, प्रमाणन और बाजार में प्रवेश करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि,यह फैसला ऐसे समय आया है,जब पश्चिम एशिया में संघर्ष और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर अनिश्चितताएं भारत सहित अनेक देशों के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं। हालांकि, यह कारनामा सही नहीं होगा कि दुनिया में तेल की भारी किल्लत होना निश्चित है। वास्तविक स्थिति संघर्ष की अवधि, तेल उत्पादक देशों की आपूर्ति, समुद्री परिवहन मार्गों और अंतरराष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। लेकिन एक बात स्पष्ट है,जो देशअपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए एक ही प्रमुख आयातित ईंधन पर निर्भर रहते हैं,वे अंतरराष्ट्रीय संकटों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।इसी चुनौती के बीच एथेनॉल भारत के लिए केवल वैकल्पिक ईंधन नहीं,बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता, कृषि आधारित उद्योग और परिवहन क्षेत्र में तकनीकी बदलाव का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है। साथियों! बात अगर हम ई 20 से ई 100 तक: आखिर क्या बदल गया? इसको समझने की करें तो,भारत में पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिलाने की व्यवस्था पहले से लागू है। ई 20 पेट्रोल में लगभग 20 प्रतिशत एथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल होता है। भारत ने 2025 में पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित समय से पहले हासिल कर लिया था। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की जानकारी के अनुसार,एथेनॉल आपूर्ति में 2024–25 में औसत मिश्रण क़रीब 19.24 प्रतिशत तक पहुंच गया था और 2025–26 में 20 प्रतिशत का स्तरहासिल किया गया। अब ई 100 की व्यवस्था इस दिशा में अगला कदम है। ई 100 का अर्थ लगभग शुद्ध एथेनॉल ईंधन है, जबकि ई 85 में लगभग 85 प्रतिशत एथेनॉल और शेष मुख्यतः पेट्रोल होता है। इन ईंधनों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए फ्लेक्स-प्यूल वाहन अलग- अलग एथेनॉल-पेट्रोल मिश्रणों पर चलने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। सरकार की नई अधिसूचना का अर्थ यह नहीं है कि भारत की सभी पेट्रोल करें अथवा ई 100 पर चल सकती हैं या पेट्रोल पंपों पर ई 100 हर जगह उपलब्ध हो गया है।फिलहाल यह बदलाव उच्च एथेनॉल मिश्रणों के लिए वाहनों के नियामकीय परीक्षण और प्रमाणन ढांचे को स्पष्ट करता है। ईंधन की व्यापक उपलब्धता और नए वाहनों का व्यावसायिक विस्तार अलगअलग चरणहैं। साथियों! बात अगर हम भारत को एथेनॉल से होने वाले चार सबसे बड़े फायदों को समझने की करें तो पहला फायदा- कच्चे तेल के आयात और विदेशी मुद्रा पर दबाव कम करना-भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के आयात से पूरा करता है। जब पेट्रोल में घरेलू स्तर पर उत्पादित एथेनॉल मिलाया जाता है,तो समान मात्रा में पेट्रोल तैयार करने के लिए आवश्यक जीवाश्म ईंधन की जरूरत घट सकती है। इससे तेल आयात बिल और विदेशी मुद्रा पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि वास्तविक बचत एथेनॉल की मात्रा, उत्पादन लागत और अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों पर निर्भर करेगी।

भारतीय दार्शनिक समुदाय

20-सर्वास्तिवाद (वैभाषिक)

गताक्त से आगे...

सर्वास्तिवाद और बाह्यार्थवाद – यथार्थ बात तो यह है कि सर्वास्तिवादी वैभाषिक को न्याय-वैशेषिक के समान बाह्यार्थवादी भी नहीं कहा जा सकता। प्रोफेसर रोजेनवर्ग की रूसी भाषा में लिखी, ‘Problems of Buddhist Philosophy’ नामक पुस्तक का हवाला देते हुये और उस विद्वान् लेखक के विचारों को उद्धृत करते हुये श्रेखात्स्की ने वैभाषिक सिद्धान्त के विषय में लिखा है:–

जो कुछ भी हो उसका अपना एक विशेष प्रकार का सिद्धान्त है जो कि साधारण बाह्यार्थवाद से सर्वथा भिन्न है, प्रत्युत कुछ आधुनिक मतों से मिलता है जिन में बाह्य और आन्तरिक (मानसिक) दोनों प्रकार की घटनाओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है और उनके बीच में एक विशेष प्रकार का सामञ्जस्य माना गया है, परन्तु यह नहीं माना गया कि उनमें एक दूसरी को (अर्थात् आन्तरिक विज्ञान बाह्यवस्तु को) ग्रहण

करती है। सारे विश्व का चलचित्र के रूप में यह निरूपण और आन्तरिक तथा बाह्य जगत् की सारी घटनाओं को, जिनसे एक व्यक्ति की जीवन-धारा बनी हुई है, क्षण भर के लिये झलकने वाले तत्त्वों के परस्पर सम्बद्ध जटिल घटना-चक्र के रूप में बदल देना-इसको किसी प्रकार भी बाह्यार्थवाद नहीं कहा जा सकता।

इसका सार यह है कि साधारणतया बाह्यार्थवाद में यह माना जाता है कि बाह्यजगत् में पदार्थों का पूर्व से अस्तित्व है और उन्हें हम अपने प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा ग्रहण करते है। परन्तु वैभाषिक के सिद्धान्त में बाह्य वस्तु का क्षण और ज्ञान का क्षण साथ-साथ उत्पन्न होते हैं और उनमें किसी प्रकार से सामञ्जस्य हो जाता है। इस प्रकार वैभाषिक का प्रत्यक्ष सिद्धान्त और बाह्यवस्तु सम्बन्धी सिद्धान्त न्याय-वैशेषिक के समान बाह्यार्थवादी से सर्वथा भिन्न है।

क्रमशः ...



ज्ञान/मीमांसा

जंतर-मंतर पर प्रतिबंध, फिर भी सड़कों पर आंदोलन

सौरभ वाणर्वय

देश में चुनावी पारदर्शिता और कथित वोट चोरी को लेकर शुरू हुआ आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। दो अक्टूबर से शुरू हुए इस विरोध प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक माहौल लगातार गर्म बना हुआ है। जंतर-मंतर जैसे निर्धारित स्थानों पर प्रदर्शन से संबंधित प्रतिबंधों और प्रशासनिक सीमाओं के बीच आंदोलन की आवाज सड़कों तक सुनाई दे रही है। विपक्षी दलों के साथ युवाओं की भागीदारी और स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखने वाले यूट्यूबर्ों तथा डिजिटल पत्रकारों की सक्रियता ने इस मुद्दे को एक नया आयाम दिया है। सवाल यह है कि क्या इस आंदोलन को केवल राजनीतिक विरोध के रूप में देखा जाना चाहिए, या फिर इसके पीछे लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति जनता के विश्वास से जुड़ी चिंताओं को भी समझने की आवश्यकता है?

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां चुनाव केवल सरकार बनाने का माध्यम नहीं, बल्कि जनता की इच्छा व्यक्त करने का सबसे महत्वपूर्ण अवसर हैं। मतदाता अपने मत के जरिए सत्ता को स्वीकार करता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे बदलने का अधिकार भी रखता है। इसलिए चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर उठने वाले सवालों को गंभीरता से सुनना लोकतांत्रिक व्यवस्था की जिम्मेदारी है। हालांकि, वोट चोरी जैसे गंभीर आरोपों को प्रमाणों और तथ्यों के आधार पर परखा जाना भी उतना ही आवश्यक है। आरोप लगाना और आरोप सिद्ध होना दो अलग-अलग बातें हैं। लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि न तो सवाल पूछने वालों को बिना सुने खारिज किया जाए और न ही बिना प्रमाण किसी आरोप को अंतिम सत्य मान लिया जाए।

किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के सामने विरोध प्रदर्शनों से निपटने की चुनौती रहती है। सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन का दायित्व है, लेकिन इस जिम्मेदारी का निर्वहन करते समय नागरिकों के शांतिपूर्ण विरोध और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान भी जरूरी है। यदि किसी स्थान पर सुरक्षा, यातायात या कानून-व्यवस्था से संबंधित प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो उनके पीछे स्पष्ट कारण होने चाहिए और उनका पालन निष्पक्ष तरीके से कराया जाना चाहिए।

सरकार की आलोचना करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को व्यस्वस्था विरोधी मान लेना उचित नहीं



है। उसी प्रकार आंदोलन के नाम पर कानून तोड़ने या आम नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित करने को भी सही नहीं ठहराया जा सकता। लोकतंत्र में सरकार और प्रदर्शनकारियों, दोनों से जिम्मेदार आचरण की अपेक्षा की जाती है।

यदि आंदोलन को लेकर यह धारणा बनती है कि सरकार असहमति की आवाज को जनता तक पहुंचने से रोकना चाहती है, तो इससे राजनीतिक अविश्वास बढ़ सकता है। दूसरी ओर, यदि आंदोलनकारी तथ्यों के बजाय केवल भावनाओं के आधार पर दावे करते हैं, तो उनकी विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है। बेहतर रास्ता यही है कि चुनावी शिकायतों की निष्पक्ष जांच हो, संबंधित संस्थाएं तथ्यों के साथ जवाब दें और जनता के सामने स्थिति स्पष्ट की जाए।

विपक्ष का काम केवल सरकार की आलोचना करना नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की जवाबदेही सुनिश्चित करना और जनता के सामने वैकल्पिक नीतियां प्रस्तुत करना भी है। यदि विपक्ष चुनावी प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाता है, तो उसे ठोस साक्ष्य, व्यवस्थित शिकायतें और तथ्यात्मक तर्कों सामने रखने चाहिए। केवल नारों और राजनीतिक आरोपों से जनता का विश्वास लंबे समय तक कायम नहीं रखा जा सकता।

साथ ही, सरकार को भी यह समझना होगा कि विपक्ष की हर आलोचना को राजनीतिक षड्यंत्र बताकर खारिज कर देना समस्या का समाधान नहीं है। लोकतंत्र में सत्तापक्ष और विपक्ष एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी अवश्य हैं, लेकिन दोनों की जवाबदेही अंततः जनता के प्रति है। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता भी इसी में है कि उसके निर्णयों, प्रक्रियाओं और शिकायत निवारण व्यवस्था पर जनता का भरोसा बना रहे।

इस आंदोलन के बीच यूट्यूबर्ओं और स्वतंत्र डिजिटल पत्रकारों की भूमिका विशेष रूप से ध्यान खींचती है। पहले समाचारों और राजनीतिक

अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन डे



अक्टूबर को मनाया जाता है, यह दिन एनिमेशन के क्षेत्र में काम करने वाले कलाकारों और निर्माताओं की कड़ी मेहनत और रचनात्मकता को मान्यता देने के लिए समर्पित है, एनिमेशन कला की विविधता और उसकी अपार संभावनाओं को दिखाने का भी इसका मुख्य उद्देश्य है।

2. इस दिन का उद्देश्य क्या है?

इस दिन का मुख्य उद्देश्य एनिमेशन कला की महत्वपूर्णता को समझाना और उसका सम्मान करना है, एनिमेशन न केवल बच्चों के लिए, बल्कि सभी आयु वर्ग के दर्शकों के लिए आकर्षक और

सूचनात्मक होता है, इसे एक कला के रूप में मान्यता देकर, इसके विकास और समृद्धि को बढ़ावा दिया जाता है।

3. अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन डे की शुरुआत कब हुई थी?

अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन डे की शुरुआत 2002 में की गई थी, जब इसे हथ्थरह्ठ द्वारा मान्यता मिली, यह दिन एनिमेशन के इतिहास और उसकी सांस्कृतिक महत्वता को रेखांकित करता है, इस अवसर पर, विभिन्न देशों में एनिमेशन के फील्ड में किए गए कार्यों को सराहा जाता है और नए प्रतिभाओं को मोटिवेट किया जाता है।

4. इस दिन कौन-कौन से कार्यक्रम होते हैं?

इस दिन कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे कार्यशालाएं, प्रदर्शनी और

फिल्म स्क्रीनिंग, विभिन्न एनिमेशन फिल्में प्रदर्शित की जाती हैं, और कलाकार अपनी रचनाओं के बारे में चर्चा करते हैं, यह अवसर एनिमेशन की तकनीकों और शैलीयों को साझा करने के लिए भी होता है, जिससे नए लोगों के विचारों का आदान-प्रदान होता है।

5. इस दिन का महत्व क्यों है?

एनिमेशन केवल मनोरंजन का एक रूप नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक संवाद और सामाजिक मुद्दों को उजागर करने का एक प्रभावशाली माध्यम है, यह बच्चों और वयस्कों दोनों को आकर्षित करता है और उन्हें नई सोच प्रदान करता है, एनिमेशन के माध्यम से सामाजिक संदेशों को सरल और रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है, जो इसके महत्व को और बढ़ाता है।

आज का इतिहास

- 1492 क्रिस्टोफर कोलम्बस ने क्यूबा के पूर्वी तट की खोज की थी।
- 1851 बंगाल मे ब्रिटिश इंडियन एसोशिएसन की स्थापना हुई थी।
- 1863 ज़िनेवा मे हुए कॉन्फ़ेस के तहत अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का गठन किया गया था।
- 1886 अमेरिका के राष्ट्रपति ग्रेोवर क्लीवर्लैंड ने फ्रांस से उपहार में मिली स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का औपचारिक अनावरण किया था।
- 1891 जापान में भूकंप से 7300 लोगों की मौत हो गयी थी।
- 1918 आस्ट्रिया और हंगरी के अलग होने के बाद चेकोस्लोवाकिया स्वतंत्र हुआ था।
- 1913 जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा की स्थापना हुई थी।
- 1922 इटली में रोम मार्च के द्वारा फासिस्ट शक्ति ने सत्ता पर अधिकार कर लिया और मुसोलीनी वहाँ का प्रधानमंत्री बना था।
- 1922 लाल सेना ने व्लादिवोस्तोक का अधिग्रहण किया था।
- 1929 वाल स्ट्रीट धराशायी हुआ था। अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट कहा जाता है।
- 1940 मोसोलीनी के नेतृत्व में देश को दो लाख की सेना ने यूनान पर आक्रमण किया था।
- 1944 दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के घटक बुलगारिया ने बिना शर्त सोवियत संघ के सामने समर्पण कर दिया था।
- 1947 जम्मू-कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने राज्य का भारत में विलय करने वाले समझौते पर सहमति जताई।
- 1950 मदर टेरेसा ने कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की।
- 1954 अर्नेस्ट हेमिंग्वे को साहित्य का नोबल पुरस्कार मिला था।
- 1955 मित्र और सऊदी अरब ने रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए थे।
- 1955 माइक्रोसाफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स का वाशिंगटन में जन्म हुआ था।
- 1998 इंटरपोल की 67वीं आम सभा अत्याधुनिक तकनीक आतंकवाद और अन्य आधुनिक संगठित अपराधों से निपटने की एक नयी रणनीति के साथ समाप्त हुआ था।
- 2001 जर्मनी के चॉंसलर गेरहार्ड श्रोडर भारत की यात्रा पर आये थे।
- 2004 बीजिंग में 4000 वर्ष पुराने मकबरों का पता लगा था।
- 2005 चेकोस्लोवाकिया देश ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी।
- 2009 पाकिस्तान के पेशावर में बम धमाके से 117 मरे, 213 घायल हुए थे।
- 2012 सीरिया में संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ, जिससे 128 लोग मारे गए थे।
- 2012 जर्मनी के सेबेस्टियन वेटेल ने 2012 का फार्मूला वन इंडियन ग्रां प्री खिताब जीता था।

पाकिस्तान की पैरवी से कश्मीर का भला कैसे होगा

कतिलाल मांडोट

जम्मू-कश्मीर की राजनीति में फारुक अब्दुल्ला लंबे समय से प्रभावशाली चेहरा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और तीन बार जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके फारुक अब्दुल्ला के राजनीतिक बयानों का असर केवल प्रदेश तक सीमित नहीं रहता, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति और भारत-पाकिस्तान संबंधों पर भी पड़ता है। उनके बेटे उमर अब्दुल्ला इस समय जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में फारुक अब्दुल्ला का हर बयान राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। हाल ही में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठाता है, इसलिए कश्मीर के लोग बचे हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली से न्याय की उम्मीद नहीं है और दुनिया के दबाव के कारण दिल्ली चुप है। उनके इस बयान ने एक बार फिर राष्ट्रीय हितों, कश्मीर की पहचान और पाकिस्तान की भूमिका को लेकर बहस छेड़ दी है।

सवाल यह है कि पाकिस्तान द्वारा कश्मीर का मुद्दा उठाने से कश्मीर के लोगों का अस्तित्व कैसे सुरक्षित रहता है? क्या पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय बयानबाजी कश्मीरियों की सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा और विकास की गारंटी है? पाकिस्तान दशकों से कश्मीर का मुद्दा उठाता रहा है, लेकिन सीमा पार आतंकवाद, घुसपैठ और हिंसा की घटनाओं ने जम्मू-कश्मीर के सामाजिक ताने-बाने को गहरी चोट पहुंचाई है। ऐसे में पाकिस्तान की पैरवी को कश्मीरियों के बचे रहने का आधार बताना तर्कसंगत नहीं लगता। फारुक अब्दुल्ला को स्पष्ट करना चाहिए कि उनके बयान का वास्तविक आशय क्या है और वे किस आधार पर पाकिस्तान की भूमिका को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं।

फारुक अब्दुल्ला के विवादित बयान कोई नई बात



नहीं हैं। नवंबर 2017 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर उन्होंने कहा था कि वह पाकिस्तान के पास है और युद्ध करने से भी स्थिति नहीं बदलेगी। इसी दौरान उन्होंने पाकिस्तान की सैन्य क्षमता और उसके परमाणु हथियारों का उल्लेख करते हुए भी बयान दिया था। इन टिप्पणियों पर देशभर में राजनीतिक विवाद हुआ। आलोचकों ने आरोप लगाया कि ऐसे बयान पाकिस्तान के पक्ष को मजबूती देते हैं। दूसरी ओर, फारुक अब्दुल्ला ने अपने रुख को वास्तविक परिस्थितियों को स्वीकार करने और युद्ध के बजाय शांति का रास्ता अपनाने की जरूरत से जोड़कर प्रस्तुत किया। यहां यह समझना जरूरी है कि शांति की वकालत करना और पाकिस्तान के दावों को स्वीकार करने का संकेत देना दो अलग-अलग बातें हैं।

जुलाई 2017 में कश्मीर विवाद के समाधान के लिए अमेरिका और चीन जैसे देशों की भूमिका पर चर्चा करने संबंधी उनके बयान ने भी राजनीतिक बहस को जन्म दिया था। भारत का आधिकारिक रुख रहा है कि जम्मू-

कश्मीर से जुड़े मुद्दे भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बातचीत से सुलझाए जाने चाहिए। ऐसे में तीसरे देशों की मध्यस्थता का सुझाव भारतीय कूटनीतिक नीति से अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। किसी भी लोकतंत्र में सरकार की विदेश नीति की आलोचना करना गलत नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय संप्रभुता से जुड़े विषयों पर बयान देते समय तथ्यों और संवैधानिक स्थिति का ध्यान रखना आवश्यक है।

अप्रैल 2017 में कश्मीर में पत्थरबाजी करने वाले युवाओं को लेकर फारुक अब्दुल्ला के बयान भी विवाद का विषय बने थे। उन्होंने युवाओं की नाराजगी और उनकी शिकायतों को समझने की जरूरत पर जोर दिया था। निश्चित रूप से युवाओं की समस्याओं को सुनना और उनके भविष्य के लिए अवसर उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। बेरोजगारी, शिक्षा और राजनीतिक भागीदारी जैसे मुद्दों पर गंभीरता से काम होना चाहिए। लेकिन युवाओं की समस्याओं को समझने और हिसक गतिविधियों को उचित ठहराने के बीच अंतर

भारत में बंगलादेश और श्रीलंका जैसे हालात पैदा करने की खतरनाक सोच

त्रिलोक कपूर/ प्रवीण बांसल

विशेष गहन पुनरीक्षण (एस.आई.आर.) पर कांग्रेस पार्टी और वामपंथी दलों द्वारा चुनाव आयोग की प्रक्रिया को लेकर फैलाया जा रहा भ्रम किसी भी स्थिति में सफल नहीं होगा। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाकर देश में राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। आज कांग्रेस और वामपंथी विचारधारा से जुड़े कुछ नेता खुलेआम ‘रिजिम चेंज’ की बात कर रहे हैं। ऐसी बयानबाजी से प्रतीत होता है कि कांग्रेस भारत में बंगलादेश और श्रीलंका जैसी राजनीतिक अस्थिरता की परिस्थितियां पैदा करना चाहती है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को असंवैधानिक दबाव के माध्यम से अस्थिर करने की किसी भी सोच का भाजपा लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेगी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहां सत्ता परिवर्तन का एकमात्र संवैधानिक रास्ता जनता का जनादेश है। किसी भी राजनीतिक दल को लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा करके देश में अराजकता का वातावरण बनाने का अधिकार नहीं है। मतदाता सूची की शुद्धता निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की बुनियादी आवश्यकता है। प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए, जबकि किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम कानून के विरुद्ध सूची में शामिल नहीं रहना चाहिए। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि देश में किसी भी गैर-कानूनी घुसपैटिए को अवैध तरीके से मतदान नहीं करने दिया जाना चाहिए। भारत के चुनावों में मतदान का अधिकार केवल कानून के अनुसार पात्र भारतीय नागरिकों को है। कांग्रेस और विपक्षी दल मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी राजनीतिक स्थिति कमजोर होने



का भय है। भाजपा लंबे समय से मतदाता सूचियों में संभावित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और सुधार की पक्षधर रही है। यदि एस.आई.आर. के माध्यम से मृत, स्थानांतरित, दोहरे पंजीकरण वाले अथवा अन्य अपात्र नामों की पहचान कर कानून के अनुसार सुधार किया जाता है, तो इसमें आपत्ति क्यों होनी चाहिए? इस प्रक्रिया में किसी भी पात्र नागरिक का मतदान अधिकार प्रभावित नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग को पारदर्शिता, उचित नोटिस और अपील के अवसर के साथ पुनरीक्षण सुनिश्चित करना चाहिए। कांग्रेस को यदि किसी प्रक्रिया पर आपत्ति है तो उसे तथ्यों और संवैधानिक माध्यमों से अपनी बात रखनी चाहिए, न कि बिना प्रमाण गंभीर आरोप लगाकर जनता में भ्रम पैदा करना चाहिए। भाजपा लोकतंत्र, संविधान और निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। देश की जनता कांग्रेस और वामपंथी दलों की कथित भ्रम फैलाने की राजनीति को समझती है तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं की कमजोर करने के किसी भी प्रयास को सफल नहीं होने देगी। लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का वोट सुरक्षित होना चाहिए और प्रत्येक अपात्र नाम की कानूनसम्मत जांच होनी चाहिए। यही निष्पक्ष चुनाव और मजबूत लोकतंत्र का आधार है।

डॉ. मोनिका भाम्मू कलाना

मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ देशभर के कई शहरों में सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन किसी एक पार्टी या विचारधारा से जुड़े हुए लोगों द्वारा आयोजित नहीं होकर, इसमें कई पार्टियां और आम जनमानस शामिल हैं। इंटरनेट मीडिया के जमाने में जब हर विरोध को हैशटैग और ट्रॉलिंग तक सीमित कर दिया जाता है वहाँ लोगों और विशेषकर अश्वर्थ से कम नहीं है। इतिहास गवाह है कि जो सरकार जिसने लम्बे वक्त तक गद्दी पर रहती है उसका अभिमान उसी अनुपात में बढ़ता जाता है समय के साथ वे जनता द्वारा दिए गए प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी भूलकर सर्वेसर्वा की भूमिका में आ जाती है।

सत्ता को यह सोचने की जरूरत है कि सड़कों पर उतरे लोग केवल एक समस्या को लेकर नहीं उतरे हैं। यह समस्या तो तात्कालिक कारण भर है। उसके पीछे उन सवालों की एक लम्बी कतार है जिनके उतर दिए बिना उन्हें ढक देने का प्रयास किया गया था। विपक्ष एसआईआर प्रक्रिया और वोट चोरी को लेकर शुरू से ही दबाव बना रहा था लेकिन जनता तब तक इस मसले पर सक्रिय नहीं हुई जब तक नीट पेपर लीक जैसी घटनाओं ने उनमें अपने भविष्य को लेकर असुरक्षा नहीं उत्पन्न कर दी। किसान आंदोलन हो या नीट परीक्षा के खिलाफ आंदोलन, अंततः सभी विरोध संस्थाओं और संसद पर घटते भरोसे के प्रतीक हैं। जब संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगते हैं तो असंतोष की महज उपद्रव कहके टालना आसान नहीं रह



जाता। कोई भी आंदोलन एक समस्या को प्राथमिक बनाकर चलता है किन्तु उसके पीछे ऐसी कई समस्याएँ जुड़ी होती हैं जिनसे आम जनता की रोजमर्रा की ज़िन्दगी प्रभावित होती है। इन आंदोलनों के सिरे असुरक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा के निजीकरण और बढ़ते चिकित्सा खर्चों से जुड़ते हैं। ये जन के भविष्य से जुड़े हैं जब भरोसा डगमगाता है तो असंतोष बढ़ना स्वाभाविक है, सभी आंदोलन इस भरोसे के छीजते जाने के संकट की ही अभिव्यक्ति हैं।

जब कोई सत्ता युवाओं को एक निश्चित फ्रेम में फिट करने की कोशिश करती है तब उसके खिलाफ उबाल आना स्वाभाविक है। जब जनता सत्ता की दिशा पहचान ले तो फिर उसे गुमराह करना आसान नहीं रह जाता। ऐसे में सत्ता को सड़क की लड़ाई के लिए तैयार रहना ही ईमानदारी को लेकर प्रश्न किए तो भले ही केन्द्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा हो लेकिन आंदोलन के तुरंत बाद ही सत्ता के प्रचार तन्त्र द्वारा आंदोलन करने वाली पीढ़ी को मूर्खता के पर्याय की तरह प्रचारित किया गया। क्या यह सब देख नहीं रहा था या सत्ता यह समझती है कि उनकी मंशा आजकल के नौजवान को कतई समझ नहीं आती? किसी छोटी लड़की द्वारा अपशब्द कहने पर उसे माफ़ी मांगने को बाध्य करने वाले परिस्थिति इससे पहले कभी देखने में

बनाए रखना भी जरूरी है। राजनीतिक नेतृत्व का दायित्व युवाओं को हिंसा से दूर करके लोकतांत्रिक रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। फारुक अब्दुल्ला ने हालिया बयान में कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों ने कभी भारतीय होने से इनकार नहीं किया और उनका भारत से जुड़ाव महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना आजाद के भारत से रहा है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि सत्ता के लिए हिंदू-मुसलमान को आमने-सामने किया गया। सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना देश के प्रत्येक राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है। लेकिन किसी भी नेता को धार्मिक आधार पर राजनीति के आरोप लगाने से पहले अपने राजनीतिक कार्यकाल और अपनी पार्टी की भूमिका पर भी आत्ममंथन करना चाहिए। कश्मीर की पहचान किसी एक धर्म, दल या नेता तक सीमित नहीं है। इसमें कश्मीरी पंडितों का विस्थापन, आतंकवाद से प्रभावित परिवारों की पीड़ा, सीमावर्ती नागरिकों की कठिनाइयां और सभी समुदायों की आकांक्षाएँ शामिल हैं।

फारुक अब्दुल्ला के बयानों की आलोचना करते समय उनके राजनीतिक विचारों और उनके समुदाय के प्रति भावनाओं को एक ही नजरिये से देखना भी उचित नहीं होगा। किसी नेता की मंशा पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने के बजाय उसके सार्वजनिक बयानों, नीतियों और उनके प्रभावों का तथ्यात्मक विश्लेषण होना चाहिए। लोकतंत्र में असहमति का अधिकार सभी को है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषयों पर जिम्मेदार भाषा का प्रयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जम्मू-कश्मीर की समस्याओं का समाधान केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से नहीं निकलेगा। केंद्र सरकार को नागरिकों की शिकायतों का निष्पक्ष समाधान

करना चाहिए, रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए और विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए। प्रदेश के राजनीतिक नेतृत्व को भी जनता के प्रति अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास, खेल और उद्यमिता से जोड़ना चाहिए, ताकि वे हिंसा तथा कट्टरता के प्रभाव से दूर रह सकें। आतंकवाद और सीमा पार से होने वाली हिंसा के खिलाफ कठोर कार्रवाई के साथ निर्दोष नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी सुनिश्चित होनी चाहिए।

फारुक अब्दुल्ला जैसे अनुभवी नेता से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने शब्दों के दूरगामी प्रभाव पर विचार करें। यदि उन्हें केंद्र सरकार की नीतियों से शिकायत है तो वे प्रमाणों और तथ्यों के साथ अपनी बात रखें। पाकिस्तान की भूमिका पर चर्चा करते समय उसके दावों के साथ उसके व्यवहार और कश्मीर के लोगों पर पड़े प्रभावों का भी निष्पक्ष आकलन होना चाहिए। पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठाता है, इसलिए कश्मीर के लोग बचे हुए हैं इस दावे का औचित्य स्पष्ट करना उनका जिम्मेदारी है।

भारत की एकता, संप्रभुता और जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के अधिकार एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। कश्मीर का भविष्य किसी दूसरे देश की बयानबाजी से नहीं, बल्कि शांति, विकास, लोकतांत्रिक भागीदारी और जनता के विश्वास से मजबूत होगा। राजनीतिक नेतृत्व को ऐसी भाषा अपनानी चाहिए जो समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करे, न कि विवादों की और गहरा बनाए। कश्मीर को पाकिस्तान की पैरवी के सहारे देखने के बजाय भारतीय लोकतंत्र की मजबूती, नागरिकों के सम्मान और विकास के आधार पर आगे बढ़ाना ही स्थायी शांति का रास्ता है।

लोकतंत्र में आंदोलन के मायने

नहीं आई। लोग तो ईश्वर को भी भरपूर गालियाँ देते हैं फिर उन्हीं लोगों के वोट द्वारा चुनी सरकार क्या ईश्वर से भी बड़ी हो गई है? एक आंदोलन जिसमें युवाओं ने लाठियों खाकर शिक्षामंत्री को इस्तीफा देने को विवश किया था उन्हीं मंत्री जी का इस्तीफे के बाद सत्ता पक्ष द्वारा पानड़ी पहनाकर स्वागत किया जाना कैसी नैतिकता है उसकी माफ़ी कहाँ मिलेगी?

मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का मामला केवल किसी पार्टी की सत्ता आने तक सीमित नहीं है। यह इस देश के नागरिकों को उपलब्ध एकमात्र अधिकार है जिससे पूरी व्य्क्त जनता जुड़ी हुई है। नागरिक अपने वोट को लेकर चिंता में हैं। मताधिकार पर आघात उनके बुनियादी अधिकारों पर आघात है। उनकी प्रतीक्षा और उम्मीदों पर आघात है। एकमात्र वोट ही है जिसके सहारे लोकतंत्र में जनता पाँच साल बाद निर्णय बदलने की स्थिति में होेती है। मतदाता को कुंठा कहकर टाला जाता रहा। अब जब युवा छात्र संगठन आंदोलनरत हैं तब सरकार जवाब देने की बजाय उन्हें हिरासत में लेने में अपनी सुरक्षा क्यों देख रही है। अब प्रश्न केवल मतदाता सूची की अनियमितताओं का नहीं रहकर सत्ता की जवाबदेही का हो गया है। लन्दन में हुए विरोध के बाद एनआरआई के माध्यम से यह अंतर्राष्टीय मंच पर भी मुद्दा बन रहा है। अब आंदोलनकारी आर-पार के मूड में आ गए हैं।

लोकतंत्र सिर्फ शासन चलाने की बहुमत आधारित प्रणाली भर नहीं है, यह व्यक्ति के सम्मान, स्वतन्त्रता और गिरिमा

की अवधारणा पर आधारित है। संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान इसीलिए किया गया कि कोई भी व्यक्त्ता बहुमत के नाम पर किसी व्यक्ति की बुनियादी स्वतन्त्रता का अपहरण न कर सके(लोकतंत्र का अर्थ सत्ता में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी से बनता है। जब प्रत्येक नागरिक का मताधिकार ही सुनिश्चित न हो तब यह भागीदारी किस आधार पर बनेगी? लोकतंत्र एक राजनीतिक विचारधारा मात्र न होकर एक जीवन-दर्शन है। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इस व्यवस्था में अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए समान मताधिकार का प्रावधान किया गया है। जब किसी लोकतंत्र में जनता की भागीदारी का बुनियादी प्रश्न ही संशय के घेरे में हो, तो आक्रोश होना स्वाभाविक है। मतदान लोकतंत्र के प्राण होते हैं। लोकतंत्र की पूरी प्रक्रिया मत और मतदान पर ही टिकी होती है। वोट के अधिकार से लोगों को महरूम करना उन्हें सरकार चुनने की प्रक्रिया से बाहर करना होता है। बेवजह वोट काटकर चुनी हुई सरकार, पूरी तरह लोगों के प्रतिनिधित्व पर नहीं टिकी होती। इस तरह सरकार स्वयं सवालों के घेरे में आ जाती है। ऐसे सवालों से घिरी सरकार प्रदर्शनकारियों पर जिस तरह की कार्रवाइयाँ कर रही है उससे सरकार को बौखलाहट ही अधिक प्रकट हो रही है। प्रदर्शनकारियों की रोज-रोज की गिरफ्तारी आखिर क्या साबित करती है? हजारों लोगों को गिरफ्तार करके देश को काबू में नहीं किया जा सकता। जब सत्ता एक आंदोलन को दबाने के लिए ऐसे निर्णय करने लगती है तब राष्ट्र का हर कोना जंतर-मंतर बन जाता है।

ट्रंप ने मस्क-सीआईए को ही कर दिया एक्सपोज?

अभिनव आकाश

इस वक अमेरिका के अंदर एक अजीब सी जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्र के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप तो दूसरी तरफ हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क। दोनों एक ही देश के हैं। दोनों मतलब एलन मस्क ट्रंप की पार्टी का समर्थन करते हैं और ट्रंप के समर्थक भी हैं एलन मस्क। 2024 के चुनाव में भी अच्छी खासी फाईंग की थी और इस वाले चुनाव में भी हजारों करोड़ रुपए की फाईंग की है। और इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है यूक्रेन। अमेरिका के भीतर महंगाई बढ़ रही है क्योंकि डीजल पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। स्टेट ऑफ होर्मुज बंद है। बाब अल मंदेब बंद है। जिसकी वजह से रूस के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा और वहां से तेल मंगाना पड़ा। अब रूस की रिफाइनरीज के ऊपर यूक्रेन हमले कर रहा है। यूक्रेन हमले कर रहा है। जिन ड्रोन से उन ड्रोन पर स्टालिंग की डिवाइस लगी हुई है। उस डिवाइस की मदद से ही यूक्रेन के ड्रोन रशिया को छेद पा रहे हैं। उसकी रिफाइनरी पर हमला कर पा रहे हैं। ऐसे में आपने पिछले दिनों खबर सुनी कि किस तरीके से स्टार लिंक ने यूक्रेन की स्पीड कम कर दी। आप जो समझते हैं ना डाउनलोडिंग करने की स्पीड इंटरनेट की या फिर कुछ सर्वर करने की स्पीड सिर्फ वही स्पीड इंटरनेट की नहीं होती है। हथियारों की एक अलग तरीके की स्पीड होती है। 100 किमी प्रति घंटा 150 किमी प्रति घंटा 200 किमी प्रति घंटा तक की स्पीड होती है। जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ही ज्यादा द्रिक्त सामने वाले देश को उस ड्रोन को इंटरसेप्ट करने में आएंगे। यहां स्टालिंग की स्पीड बहुत ज्यादा थी। लगभग 200 कि.मी. प्रति घंटा के आसपास थी। तो रशिया के इंटरसेप्टर उन्हें पकड़ नहीं पाते थे और ये ड्रॉस जाकर रिफाइनरी को हिट कर रहे थे। ट्रंप को रूस के साथ डील करनी थी। ऐसे में अब उन्होंने आदेश दिया या नहीं दिया। ऐसे में अचानक से यूक्रेन की स्पीड इंटरनेट वाली कम हो गई। आरोप लगा कि मस्क ने यूक्रेन के मिलिट्री स्टालिंग की स्पीड को 100 मील प्रति घंटा पर कैप कर दिया। मतलब 100 मील प्रति घंटा का मान लीनिंग कि 160 किमी प्रति घंटे के हिसाब से कैप कर दिया। कैप करने का



मतलब है अगर वो ड्रोन 160 कि.मी. प्रति घंटा की स्पीड से ऊपर जाएगा तो वो उसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो बंद हो जाएगी। उसका इंटरनेट कनेक्शन डट जाएगा। जाएगा। अब जब इंटरनेट कनेक्शन टूट जाएगा तो उसे पता नहीं चलेगा कि कहाँ हिट करना है, कहाँ हिट नहीं करना है। और जो उसे ऑपरेट कर रहे हैं लोग उनके पास तक वीडियो जब नहीं पहुंचेगा तब वो लोग भी एक तरीके से अंधे हो जाएंगे। तो ये पूरा गेम किया गया।

इससे यूक्रेन के हमलावर ड्रोन रूस के सामने फेल होने लगे और अब वॉल स्ट्रीट जनरल की ब्रेकिंग रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप ने खुद मस्क को फोन करके कहा कि यह पाबंदी हटा लो। ट्रंप का कहना है कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। एलन मस्क का कहना है कि मेरा भी उसमें कोई रोल नहीं है। रोल सामने आया सीआईए का। स्टार लिंक से डायरेक्ट इंटरनेट नहीं लेता है यूक्रेन। ये लेता है स्टार शीलड से। स्टार शीलड के ऊपर मतलब कौन नजर रखता था या फिर किसके हाथ में स्टार शीलड है। स्टार शीलड हाथ में है सीआईए के। अब पूरा गेम आपको समझ आया आ गया होगा कि किस तरीके से सिर्फ एक खबर बाहर आने से कि ट्रंप ने खुद मस्क को फोन करके कहा कि यह पाबंदी हटा लो। यहाँ सीआईए का भी जो पर्दाफाश हो गया और एलन मस्क भी एक्सपोज हो गए। वॉल स्ट्रीट जनरल के मुताबिक यह फोन बुधवार को किया गया। ट्रंप ने मस्क से कहा कि वो इस स्पीड लिमिट से नाराज हैं। यह लिमिट 14 अक्टूबर को स्पेस यान्स ने लगाई थी।

यूक्रेन को शक है कि ट्रंप ने रूस की तरफ झुकाव का हिस्सा था। क्योंकि पिछले हफ्ते ही ट्रंप ने मॉस्को से तेल खरीदने और जेलस्की को हटाने की बात कही थी। कारनेगी एंडोमेंट के एक्सपर्ट माइकल कॉफ़मैन का कहना

है कि अगर यह श्रटल नहीं हटा तो रूस का फंट लाइन पर आगे बढ़ना फिर तेज हो जाएगा। मतलब यूक्रेन की जंग का रिमोट कंट्रोल आज भी एक प्राइवेट कंपनी और दो लोगों के फोन कॉल पर टिका हुआ है। ट्रंप अब कतई नहीं चाहते कि जेलस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति रहे और वो उन्हें हटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दो हफ्ते पहले तक राहुल गांधी देश में चुनाव चोरी, वोट चोरी, ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा इन सब की मांग कर रहे थे। संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करने के आरोप बीजेपी और सरकार पर वह लगा रहे थे। पूरा विपक्ष एक साथ आ गया था। सिर्फ आरोप नहीं लगाया जा रहा था। दिल्ली में आकाशवाणी से लेकर राजघाट तक, राष्ट्रपति भवन से लेकर जंतरमंतर तक जमकर प्रदर्शन हुए। सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालकर सरकार और पूरे संवैधानिक सिस्टम पर सवाल खड़े करने की कोशिश हुई। वैसे तो आप ये कह सकते हैं कि सरकार को कटघरे में खड़ा करना हर विपक्षी का अधिकार है। सरकार ट्रैक पर रहे यह याद दिलाना विपक्ष का काम है। लेकिन संवैधानिक संस्थाओं को इस तरीके से डिसक्रेडिट कर देना कहाँ तक जायज है? राहुल गांधी ने देश में बड़ा नरैटिव खड़ा कर दिया था। सरकार पर सवालों की झड़ी लगा दी। राहुल गांधी फ्रंट फुट पर खेल रहे थे। बीजेपी, सरकार और बाकी तमाम को आकर बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देना पड़ रहा था हर चीज पर। लेकिन जैसे ही इस पूरे सियासी गेम में पीएम मोदी की एंट्री हुई पूरा समीकरण 360 डिग्री चेंज हो गया। पूरा सिस्टम ऐसे पलटा कि अब बीजेपी के सवालों पर कांग्रेस को सफाई देनी पड़ रही है। यह सब बदला है। 18 अक्टूबर को राहुल गांधी के वियतनाम जाने की खबर सामने आने के बाद। राहुल गांधी जैसे ही विदेश पहुंचे, बीजेपी को उनकी विदेश यात्रा और विदेशों में मुलाकातों पर सवालों की झड़ी लगाने का मौका मिल गया। 2020 हो, 22 हो, 24 हो, 25 हो, 26 हो, हर बार एक बड़ा मुद्दा राहुल गांधी लेकर आते हैं। भारत यात्रा पर निकलते हैं। छात्रों की गुंज करते हैं। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पीएम मोदी के घर के बाहर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही चीज मोमेंटम पकड़ती है, वो चले जाते हैं। जनता को जुटाते हैं और फिर वर्क फ्रॉम विदेश पर निकल जाते हैं।

राहुल गांधी बरी, भाजपा की रणनीति पर सवाल

सनत जैन

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए अदालत से राहुल गांधी को मानहानि के मामले में राहत मिलना, भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक रणनीति पर सवाल खड़े करता है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी से जुड़े इस मामले में जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को शिकायत दर्ज कराई थी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए भाषण से जुड़े इस प्रकरण में राहुल गांधी लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। अदालत के फैसले ने एक बार फिर यह बहस तेज कर दी है, राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मानहानि एवं अन्य मुकदमों का इस्तेमाल, आखिर किस हद तक और कितने समय तक राजनीतिक लाभ दे सकता है? राहुल गांधी के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में कई मामले दर्ज हुए। पुणे में सावरकर के परपोते द्वारा दायर मानहानि का मामला भी चर्चित है। राहुल गांधी ने दर्ज मामलों में माफ़ी मांगने के बजाय कानूनी लड़ाई लड़ने का रास्ता चुना। गुजरात की एक अदालत से दो साल की सजा मिलने के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई थी। उन्हें सरकारी बंगला खाली करना पड़ा था। बाद में सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक मिलने के बाद उनकी सदस्यता बहाल हुई। इन घटनाओं ने राहुल गांधी को राजनीतिक संघर्ष के लिए नई ताकत दे दी। 2014 से 2019 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता चरम पर थी। भाजपा ने अच्छे दिन, रोजगार, विकास और बेहतर जीवन के बड़े-बड़े वादे किए। समय के साथ इन वादों के क्रियाचरण, बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक चुनौतियों को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। दूसरी ओर, राहुल गांधी ने पिछले कुछ वर्षों में संसद से लेकर सड़कों तक सरकार को चुनौती दी जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा और जनहित के मुद्दों पर उनकी सक्रियता ने उनकी राजनीतिक छवि को पूरी तरह से बदलने का काम किया है। जिस नेता को भाजपा के समर्थक लंबे समय तक पणू कहकर

उपहास का विषय बनाते रहे, वही अब विपक्ष के प्रमुख चेहरे के रूप में प्रधानमंत्री मोदी को सशक चुनौती दे रहा है। विरोधियों पर लगातार निशाना साधने की रणनीति समय के साथ उलटा असर भी डालती है। मुकदमों और राजनीतिक हमलों के बीच राहुल गांधी की सक्रियता ने उनके समर्थकों के साथ-साथ कुछ अन्य वर्गों में राहुल गांधी के प्रति सहानुभूति एवं सशक्त नेता की छवि बना दी है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर देश में बहस चल रही है। इससे लगभग 40 करोड़ मतदाता प्रभावित हुए हैं। जिन्हें मतदाता सूची में नाम बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग के दफ्तर में बार-बार चक्कर काटने पड़े हैं। मतदाता सूची की शुद्धता पारदर्शिता, दस्तावेजों की जांच और पात्र मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर उठ रहे सवालों ने सरकार भाजपा और चुनाव आयोग की निष्पक्षता और उनकी लोकप्रियता पर गहरा आघात किया है। युवा पीढ़ी, विशेषकर जेनरेशन जेड, अब राजनीतिक दावों को आंख मूंदकर स्वीकार करने के बजाय सवाल पूछ रही है। धार्मिक ध्ववीकरण को पूरी तरह से नकार रही है। रोजगार, शिक्षा, महंगाई और नागरिक अधिकारों को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों की सक्रियता सरकार और भाजपा के लिए नई चुनौती बन गई है। भाजपा को यह समझना होगा, हर राजनीतिक विवाद को भवनात्मक मुद्दा बनाना या विरोधियों पर व्यक्तिगत हमले करके हमेशा चुनावी लाभ नहीं पाया जा सकता है। लोकतंत्र में जनता का विश्वास काम, जवाबदेही और विश्वसनीयता से बनता है। जिस दांव से पहलवान एक बार जीता है, जरूरी नहीं कि हर बार उसी दांव से जीत हासिल हो। सामने वाला पहलवान भी दांव-पेच पहचानकर अपनी रणनीति बदलता है। राहुल गांधी की राजनीतिक चुनौती को केवल उपहास या मुकदमों के नजरिये से देखना भाजपा की बड़ी भूल हो सकती है।

दफ्तर में खान-पान का रखें विशेष ध्यान

आज के इस बदलते परिवेश में जहां हर महिला, पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। वहीं दूसरी ओर इस वजह से वह कई बीमारियों के चपेट में भी लगातार आती जा रही है। आज हर महिला और पुरुष को जीवन ज्यादातर दफ्तर में ही बीतता है। शायद यही कारण है कि दफ्तर का व्यस्त शेड्यूल, शिफ्ट ड्यूटी और काम का बहुत ज्यादा दबाव आपके मानसिक स्वास्थ्य के साथ-साथ शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालता है। ऐसे में दफ्तर के दौरान खान-पान का सही ख्याल आपको स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है, आइए जानते हैं दफ्तर में क्या खाएं और क्या ना खाएं।

कैसा हो आहार
दफ्तर में आपकी प्राथमिकता काम है न की आपका आहार, इसलिए आपका आहार ऐसा होना चाहिए, जो आपको ताकत दे, न कि ऐसा, जिसे खाकर आपको नींद आए। दफ्तर में लंच के दौरान अपनी प्लेट को न भरें। सही मात्रा में संपूर्ण आहार लें। साथ ही दफ्तर में लंच कभी भी छोड़ें नहीं। ऐसा करने से आपका ध्यान काम पर नहीं, बल्कि खाने पर ही लगा रहेगा।

अपने आहार में इन बातों का ध्यान रखें:
भोजन में सलाद जरूर लें, शरीर में ऑक्सीजन की कमी की समस्या से बचने के लिए भोजन में ज्यादा से ज्यादा सलाद का प्रयोग करें। सलाद और अंकुरित अनाज हल्का आहार होता है, जिसका सेवन आपको नींद से दूर रखता है और दफ्तर में काम के दौरान आपको सक्रिय भी रखता है।

शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है दही
दही के रोजाना सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। दही के बैक्टीरिया तथा पोषक तत्व शरीर के लिए एंटीबायोटिक का कार्य करते हैं और रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता भी बढ़ाते हैं। इससे आप बीमारियों से दूर रहते हैं।

ताजे फल रखेंगे आपको तराताजा

ताजे फल न केवल आपको तराताजा रखते हैं, बल्कि आपकी सेहत को फिट भी रखते हैं। ताजे फलों का सेवन आपके दिन को बेहतर बनाता है। दफ्तर में छोटे से ब्रेक के दौरान एक फल का सेवन आपको स्वस्थ रखता है और काम को ऊर्जा से भर देता है।

नाइट शिफ्ट में रखें इन बातों का ध्यान
रात के वक्त बिना मिर्च-मसाले के आहार का सेवन करें, इससे अल्सर, कब्ज, एसिडिटी जैसी समस्याओं से दूर रहेंगे।

नाइट शिफ्ट के दौरान एल्कोहल और सिगरेट का सेवन न करें।
रात में काम के दौरान खुद को रिलेक्स करने के लिए संगीत सुनें और मेडिटेशन करें।

नियंत्रित रखती है ग्रीन टी
इसके सेवन से कई बीमारियों पर नियंत्रण किया जा सकता है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। ग्रीन टी में एमीनो एसिड होता है, जो एंग्जाइटी और स्ट्रेस से छुटकारा दिलाने में सहायक होता है। दफ्तर में जब भी मौका मिले ग्रीन टी जरूर पीएं।

कार्बोहाइड्रेट कम फाइबर ज्यादा
फाइबरयुक्त आहार जैसे साबुत अनाज ब्रेन न्यूरोट्रॉफिक सेरोटोनिन के उत्पाद को बढ़ाता है, जो आपके सोचने-समझने की शक्ति को बढ़ाता है और तनाव को कम करने में मदद करता है। हरी, पीली और नारंगी रंग की सब्जियां में मिनरल्स, विटामिंस और फाइटोकेमिकल्स होते हैं, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। जबकि कार्बोहाइड्रेट के सेवन से आपको नींद आती है, इसलिए दफ्तर में ज्यादा रोटी और चावल का सेवन न करें।

स्मोकिंग के बाद सौफ जरूर खाएं
स्मोकिंग आपके स्वास्थ्य और काम, दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, इसलिए काम के दौरान स्मोकिंग से बचने के लिए मुंह में इलायची या सौंफ रखें।

इससे आपकी स्मोकिंग भी कम होगी और ये चीजें आपको नुकसान भी नहीं देंगी।

पानी ज्यादा पीएं
दिन भर में जितना हो सके उतना पानी पीएं, क्योंकि आप अंदर से हाइड्रेट रहेंगे तो ताजगी भरा महसूस करेंगे और आपको तनाव के कारण सिरदर्द जैसी परेशानियां भी नहीं होंगी। भरपूर मात्रा में पानी पीने से आपका सिस्टम साफ रहता है और आप तनाव से कोसों दूर रहते हैं। नींबू पानी, नारियल पानी और ताजे फलों के रस का भी सेवन कर सकते हैं।



काजल से बनाएं आंखों को खूबसूरत

अक्सर लोग किसी महिला की खूबसूरती बयां करते वक्त उसकी गमगीन आंखें जरूर देखते हैं और हर खूबसूरत आंखें लोगों को विशेष तौर पर आकर्षित करती है। तो यह ज़रूरी है कि आप अपनी त्वचा के साथ-साथ अपनी आंखों पर भी विशेष तौर पर ध्यान दें। आंखों की खूबसूरती के लिए काजल और आईलाइनर आज मेकअप का अहम हिस्सा बन गए हैं। लेकिन इस पर भी वक्त की मार पड़ी है। जिसके साथ-साथ काजल के रूप भी बदल गए हैं। आपकी आंखें खूबसूरत हैं और उनकी खूबसूरती में और इजाफा आप काजल और आईलाइनर से कर सकती हैं। कैसे चुनें अपना आई मेकअप और इस्तेमाल के दौरान किन बातों का ध्यान रखें, आइए जानते हैं।

पेंसिल और रैक्टेबल आईलाइनर: ये सबसे कॉमन और ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाले आईलाइनर और काजल हैं। इन्हें प्रयोग करना भी बेहद आसान है, इसलिए युवतियों को ये ज्यादा पसंद आते हैं। आसानी से इन्हें आंखों के अंदर से बाहर की तरफ लगाया जा सकता है। पेंसिल की मदद से आप किसी भी तरह का आकर्षक मेकअप कर सकती हैं।

जेल: अगर काजल की कोई भी स्टाइल ढूंढ़ रही हैं तो जेल सबसे बढ़िया विकल्प हो सकता है। यह बेहद स्मूद व हल्का होता है। काजल लगाते समय आपसे गड़बड़ी भी हो गई तो इस काजल के साथ आसानी से उसे मैनेज कर सकती हैं। जेल काजल की मदद से आई मेकअप में तमाम तरह के प्रयोग कर सकती हैं।

लिविड: मेकअप के कुछ बेहतरीन तरीके बीसवीं-

चालीसवीं सदी से प्रेरित होकर अभी तक चलन में हैं। बाकी सभी काजलों की तुलना में यह बहुत साधारण है। इसे लगाने में बहुत कम समय लगता है, इसलिए महिलाओं में इसे ज्यादा पसंद किया जाता है।

क्रीम: क्रीमी काजल और आईलाइनर का कोई जवाब ही नहीं है। यह काजल आंखों की प्राकृतिक खूबसूरती को और निखारता है। आंखों पर लगाने के साथ ही यह काजल सूख जाता है और आंखों की खूबसूरती बढ़ा देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह काजल ढेरो रंग व वेरायटी के साथ बाजार में मौजूद है।

काजल: आंखों को सजाने का यह सबसे पुराना और सस्ता साधन है। यह केवल आंखों को ही नहीं सजाता, बल्कि आपकी आंखों को कई तरह के इफेक्शन से भी बचाता है।

कोल: यह काजल पेंसिल व रैक्टेबल आईलाइनर के समान ही है। इन दोनों के मुकाबले यह थोड़ा ज्यादा गाढ़ा व क्रीमी है। गाढ़ा होने के कारण आंखों का सबसे सुंदर मेकअप इसी काजल से निखर कर आता है। कोल काजल आंखों की दोनों वॉटरलाइनों पर आउटलाइन करने के लिए भी सबसे अच्छा माना जाता है।

सावधानी जरूर बरतें
बाजार में इन दिनों काजल व आईलाइनर्स की ढेरों वेरिएटी और ब्रांड मौजूद हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर फबने वाला एक बेहतरीन क्वालिटी का आईलाइनर और काजल पसंद करना है। इन दिनों ब्रांड के नाम पर घटिया व नकली काजलों की भरमार है। ज्यादा पुराना काजल कटई इस्तेमाल न करें।



अच्छी सेहत के लिए जरूरी है पौष्टिक आहार

अक्सर यह देखा जाता है कि कई लोग कितना भी खा लें उनकी सेहत पर जरा भी असर नहीं पड़ता और कई लोग अपनी सेहत में अंतर लाने के लिए तरह-तरह के उपाय करते रहते हैं। लेकिन हम कभी भी यह नहीं सोचते कि जिसका हम प्रतिदिन सेवन करते हैं, उसमें पौष्टिकता कितनी है। आइए कुछ रोचक तथ्यों पर नजर डालें जो हमारे भोजन की पौष्टिकता और स्वाद दोनों को ही सन्पूर्ण मात्रा में बढ़ा सकते हैं। सेहत और सुंदरता दोनों के लिए यह जानकारियां उपयोगी हैं-

क्या आप जानते हैं, खाने-पीने की चीजों में शुगर की कितनी मात्रा होनी चाहिए। आप यह जान लें कि 200 मिली कोला में लगभग 22 ग्राम शर्करा होती है, जबकि इतनी ही चॉकलेट सोया मिल्क में 10 ग्राम शर्करा होती है। मार्केट में मौजूद स्प्रेड्स ड्रिंक के 200 मिली कप में 21 ग्राम शर्करा होती है। इंस्टेंट शुगर से मीठी चाय की 200 मिली मात्रा में 21 ग्राम शर्करा होती है।

महिलाएं अक्सर घर के कामकाज में अपना सुबह का नाश्ता भूल जाती हैं। ऐसा करना ठीक नहीं है। जो लोग सुबह का नाश्ता नहीं करने की रूटीन बना लेते हैं, उनमें टाइप-2 डायबिटीज की आशंका अधिक हो जाती है।

खाना बनाने समय कुछ बातों का ख्याल रखें। मीट को धीमे-धीमे और कम आंच पर पकाएं। कोशिश करें कि स्टीम करके पकाई जाने वाली चीजों को फ्राई या ग्रिल नहीं करें। डाइट संबंधित ऐसे टिप्स आपको जवां रखने में मददगार होंगे।

नाश्ते में साबुत अनाज को जरूर शामिल करें। इसमें पोलिफिनॉल नामक एंटी ऑक्सीडेंट काफी मात्रा में होता है।

पॉपकॉर्न को इस मामले में काफी स्मार्ट माना जा सकता है। इसमें दूसरे प्रोसेस्ड स्नेक्स जैसे चिप्स की तुलना में 5 गुना अधिक एंटी ऑक्सीडेंट पाया जाता है।

अलसी में बुलनशील और अघुलनशील 2 तरह के फाइबर होते हैं। इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड भी होता है। इसे खाने में कई तरह से प्रयोग करें। इसे फलों के स्मूदी में मिलाकर पीएं या पकी सब्जियों में डालकर बनाएं। आटे में मिलाकर इसकी रोटियां भी बना सकती हैं।

शहर के अच्छे-अच्छे स्टोर्स में सोया मिल्क आसानी से मिल जाता है। यह फलेवर वाला और बिना फलेवर के भी मिलता है। अगर आप प्रिजर्वेटिवरहित सोया मिल्क को अपने खाने में शामिल करना चाहती हैं, तो सोया को रातभर के लिए पानी में भिगोएं। दूसरे दिन इसे ग्राइंड करके इसका दूध निकाल लें। एक गिलास सोया मिल्क में प्रोटीन की मात्रा लगभग उतनी ही होती है, जितनी कि एक गिलास गाय के दूध में होती है। 200 मिली सोया मिल्क में 80 कैलोरी और लगभग 6.6 ग्राम प्रोटीन होता है।

दिल्ली के चांदनी चौक में भाजपा आज निकालेगी मार्च

नईदिल्ली। बुधवार, 28 अक्टूबर को दिल्ली के चांदनी चौक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ नाम से एक पैदल मार्च का नेतृत्व करेंगे। विपक्षी दलों द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर किए जा रहे विरोध के बीच, बीजेपी अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए यह कदम उठा रही है। इस मार्च में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, सांसद और पार्टी के अन्य नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। यह मार्च आज शाम करीब 4 बजे शुरू हो सकता है। इसमें 15,000 से अधिक लोगों के हिस्सा लेने की संभावना है। बीजेपी का यह मार्च चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच हो रहा है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की अन्य पार्टियों ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण में गड़बड़ी का आरोप लगाया है और चुनाव आयोग पर वोट चोरी में मदद करने का इल्जाम लगाया है।

भाजपा के मार्च पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का तंज

नईदिल्ली। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने नई दिल्ली में लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ मार्च की घोषणा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की है। उन्होंने सड़कों पर होने वाले विरोध प्रदर्शनों और स्थानीय व्यवसायों पर उनके असर को लेकर बीजेपी के कथित दोहरे मापदंडों पर सवाल उठाया है। विपक्ष के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों से व्यापार में बाधा आने और व्यापारियों को नुकसान होने के आरोपों का जवाब देते हुए, खेड़ा ने केंद्र सरकार को चुनौती दी और पूछा कि आप उनसे पूछिए कि क्या व्यापारियों को नुकसान होगा या फायदा? क्या बीजेपी का मार्च व्यापारियों को फायदा पहुंचाता है, और कांग्रेस का मार्च नुकसान कराता है? खेड़ा की ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब तनाव बढ़ रहा है और राजधानी में बीजेपी तथा विपक्षी दल बड़े सार्वजनिक प्रदर्शनों की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी का मार्च विपक्षी प्रदर्शनों का जवाब देने के लिए है; बीजेपी का कहना है कि इन विपक्षी प्रदर्शनों से

राहुल गांधी की बढ़ी मुश्किलें सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य लोगों को नोटिस जारी कर एक याचिका पर जवाब मांगा है। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की ओर निकाले गए मार्च के दौरान राहुल गांधी ने एक गर्भवती महिला पत्रकार को धक्का दिया था। याचिका में इस मामले में प्रारंभिकी दर्ज करने और पीड़िता को मुआवजा देने की मांग की गई है। यह मामला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ के सामने रखा गया। वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने अदालत को बताया कि पहले से लंबित एक याचिका में इस मामले को लेकर आवेदन दिया गया है। इसके बाद अदालत ने राहुल गांधी और अन्य संबंधित लोगों से जवाब मांगा। याचिका में दावा किया गया है कि मार्च के दौरान राहुल गांधी ने महिला पत्रकार को गेट की तरफ जोर से धक्का दिया, जिससे उसका स्तुलन बिगड़ गया और वह गिरने लगी।

पंजाब विधानसभा के बाहर आप-कांग्रेस में भिड़ंत

चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के अंतिम दिन मंगलवार को सुखपाल सिंह खैरा के निलंबन को लेकर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक को विधानसभा में प्रवेश नहीं दिए जाने के विरोध में पार्टी विधायकों ने प्रदर्शन किया। विधानसभा परिसर में मीडिया को बयान देने के दौरान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के विधायक आमने-सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई और धक्कामुक्की की स्थिति बन गई। इससे विधानसभा परिसर में तनाव बढ़ गया। कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को 23 अक्टूबर को सदन की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया था। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने खैरा पर विधानसभा अध्यक्ष के प्रति असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने और सदन की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाते हुए निलंबन का प्रस्ताव पेश किया था। सदन में मौजूद सदस्यों ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया था। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताया हुए विरोध किया था।

मायावती ने नेताओं की अमर्यादित बयानबाजी पर जताई चिंता

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के एक विवादित बयान और विरोधस्वरूप भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के देशव्यापी प्रदर्शन के बीच मंगलवार को सभी राजनीतिक दलों की अशोभनीय टीका-टिप्पणी व बयानबाजी की बढ़ती हुई होड़ को अनुचित करार दिया है। बसपा प्रमुख मायावती ने अपने आधिकारिक एक्स पर एक पोस्ट में कहा, भारतीय राजनीति में आपसी विश्वास, द्वेष, कड़ुता, आरोप-प्रत्यारोप आदि का स्तर, गिरते-गिरते अब व्यक्तिगत स्तर पर भी काफी बेलागम होकर असंसदीय, अमर्यादित, अपमानजनक, संकीर्ण व जातिवाद से प्रसिंत होता हुआ, हिंसक बयानबाजी तक पहुंच जाना अत्यंत दुःखद है। उन्होंने कहा कि यह देश की गरिमा व मान-मर्यादा आदि के लिए भी अति-चिन्तनीय है। मायावती ने कहा, शीर्ष स्तर पर असौजन्य को भले ही एक-दूसरे के प्रति समुचित सम्मान नहीं हो, लेकिन आपत्तिजनक एवं विषैली राजनीति को अवश्य ही किसी भी प्रकार से बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का निलंबन मामला

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने के लिए दिया 10 दिन का समय

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उन याचिकाकर्ताओं को 10 दिन का समय दिया, जिन्होंने वोट चोरी के आरोपों के बीच मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित गड़बड़ियों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं को भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआर) के उन हलफनामे का जवाब देना है, जिसमें आयोग ने पूरे देश में चलाए गए एस एसआईआर अभियान का बचाव किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्य कांत, और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की तीन-सदस्यीय पीठ ने इस मामले की सुनवाई टाल दी है और अब इसके 17 नवंबर को सूचीबद्ध होने की उम्मीद है। इसके अलावा, शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को उन सभी याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है, जिनमें ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग की गई है। इनमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं द्वारा दायर याचिकाओं भी शामिल हैं।

यह घटनाक्रम चुनाव आयोग द्वारा एक हलफनामा दाखिल करने के एक दिन बाद हुआ है। आयोग ने अपने हलफनामे में एसआईआर अभियान का बचाव करते हुए कहा है कि सभी फैसले आयोग की तीनों



सदस्यों की सर्वसम्मति से लिए गए थे। आयोग ने इन आरोपों को भी खारिज कर दिया कि मतदाता पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 6 में कोई बदलाव किया गया था। चुनाव आयोग ने अपने 248 पन्नों के जवाब (हलफनामे) में इन आरोपों को गलतफहमी पर आधारित बताते हुए याचिकाओं को तुरंत खारिज करने की मांग की है। हलफनामे के अनुसार, 24 जून 2025, 27 अक्टूबर 2025 और 14 मई 2026 को जारी एसआईआर संबंधी आदेश, संविधान के अनुच्छेद 324 और मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की धारा 18 के अनुपालन में सर्वसम्मति से लिए गए थे।

चुनाव आयोग ने कहा कि किसी फाइल पर काम चलने के दौरान किसी आयुक्त द्वारा दिया गया कोई सुझाव, टिप्पणी या सवाल, आयोग का फैसला नहीं

माना जाएगा। आयोग ने बताया कि फाइलें पहले एक चुनाव आयुक्त के पास जाती हैं, फिर दूसरे के पास और अंत में मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) के पास; और जिन फैसलों को मंजूरी मिल जाती है, उन पर तीनों के हस्ताक्षर होते हैं। आयोग ने कहा कि जहां तुरंत आदेश देने की जरूरत हो और सदस्य व्यक्तिगत रूप से मौजूद न हों, वहां इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मंजूरी ली जाती है और बाद में उसे फाइल में दर्ज कर लिया जाता है। चुनाव आयोग का यह हलफनामा उन याचिकाओं के जवाब में था, जो इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के बाद दायर की गई थीं। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि एसआईआर ड्राइव को लेकर आयोग के सदस्यों के बीच मतभेद हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर, गांधी और इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने इस मामले पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

एक नवंबर को दिल्ली चलो मार्च की तैयारी

रामलीला मैदान का जायजा लेने पहुंचे कांग्रेस नेता

नई दिल्ली। कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक में शामिल अन्य विपक्षी दल एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली करने की तैयारी कर रहे हैं। इस रैली के जरिए विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करारणा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मंगलवार को दिल्ली के नेताओं के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा कि रैली की तैयारियों के लिए दिल्ली के सभी प्रमुख नेता मौके पर मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि वेणुगोपाल के पहुंचने के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं को आगे की तैयारियों के लिए निर्देश दिए जाएंगे। खेड़ा के मुताबिक, कार्यक्रम में इंडिया गठबंधन के साथ देश के विभिन्न हिस्सों से अन्य लोग भी शामिल होंगे।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने इंडिया ब्लॉक की रैली से पहले प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों में बाधा डाली। उन्होंने कहा कि पार्टी ने पहले अशोक होटल के लॉन में कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन पुलिस के हस्तक्षेप के बाद अनुमति नहीं मिली।

वेणुगोपाल के अनुसार, इसके बाद दूसरे स्थान पर कार्यक्रम के लिए जरूरी ढांचा तैयार कर रहे पार्टी कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने रोक दिया। उन्होंने कहा कि 30 अक्टूबर को प्रस्तावित कार्यक्रम एक नवंबर की रैली और मार्च की से पहले आयोजित किया जाना था।

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विपक्ष को मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के मुद्दे उठाने से रोकने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा,



हम उनके दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। हमें पता है कि कार्यक्रम कैसे करना है। वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन रोकने के लिए केंद्र सरकार दिल्ली पुलिस पर दबाव डाल रही है। वेणुगोपाल ने दावा किया कि पार्टी को 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक रामलीला मैदान के लिए अनुमति मिली थी। इसके बावजूद, उनके मुताबिक, सप्ताहांत में कार्यक्रम के लिए ढांचा तैयार करने पहुंचे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया। उन्होंने कहा, हमें नहीं पता कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह एक छोटे से जमावड़े से भी इतने डरे हुए क्यों हैं। हमने ज्ञानेश कुमार के सार्वजनिक महाभियोग की घोषणा की थी। हमने एक नवंबर को मार्च निकालने की योजना बनाई थी। पुलिस ने हमारे लोगों को ढांचा तैयार करने से रोक दिया। इसका मतलब है कि यह दिल्ली पुलिस का फैसला नहीं है। यह प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का फैसला है। वे ज्ञानेश कुमार को बचा रहे हैं।

कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के दल विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि एक ओर वास्तविक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस मुद्दे पर विरोध करने वालों को भी रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपने आंदोलन को जारी रखेगा।

उन्होंने कहा, हम कहीं भी विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। दिल्ली में कई जगह हैं। दिल्ली पुलिस हमें कैसे रोक सकती है? हमारा लक्ष्य स्पष्ट है। जब तक ज्ञानेश कुमार को पद से हटाया नहीं जाता और देश की चुनाव व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया जाता, हम शांत नहीं बैठेंगे।

कांग्रेस के मुताबिक, एक नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाले कार्यक्रम में करीब 21 राजनीतिक दलों के शामिल होने की उम्मीद है। विपक्ष गठबंधन ने इस आयोजन को कथित चुनावी अनियमितताओं और वोट चोरी के आरोपों के खिलाफ अपने अभियान का हिस्सा बताया है।

विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रतीकात्मक सार्वजनिक महाभियोग जैसी कार्रवाई की योजना बनाई है। इसके बाद रामलीला मैदान में बड़ी जनसभा और दिल्ली चलो मार्च प्रस्तावित है। वेणुगोपाल ने कहा कि पुलिस की ओर से कथित बाधाओं के बावजूद विपक्ष अपना विरोध जारी रखेगा। हालांकि, कार्यक्रम के आयोजन को लेकर आगे की राजनीति की घोषणा कांग्रेस की ओर से की जानी है।

स्टेल प्रमुख समाचार

भारत ने न्यूजीलैंड को तीसरे टी20 मैच में 6 विकेट से हराया

वेलिंगटन। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के तीसरे मुकाबले में 6 विकेट से शानदार जीत दर्ज की है। वेलिंगटन के हैनरी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 198 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम ने अभिषेक शर्मा के तूफानी शतक और वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक पारी के दम पर महज 13.1 ओवर में 199 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है।

भारत की जीत के सबसे बड़े हीरो सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा रहे। उन्होंने महज 38 गेंदों में 113 रन की तूफानी पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 11 छक्के और 9 चौके निकले। अभिषेक ने मैदान के चारों ओर बड़े शांत लगाकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को दबाव में ला दिया। यह उनके टी20 करियर का चौथा शतक रहा।

अभिषेक ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और भारतीय टीम को लक्ष्य के करीब पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। उनकी बल्लेबाजी के सामने न्यूजीलैंड के गेंदबाज विकेट लेने के बावजूद रन गति पर अंकुरण नहीं लगा सके। इस शानदार प्रदर्शन के लिए अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए महज 19 गेंदों में 45 रन बनाए। उनकी पारी में 4 चौके और 4 छक्के शामिल रहे। अभिषेक और वैभव ने मिलकर भारतीय पारी को ऐसी शुरुआत दी कि मुकाबला शुरुआती ओवरों में ही एकतरफा होता नजर आया। 199 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने आक्रामक शुरुआत की और 13.1 ओवर में 199/3 का स्कोर बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया।

आर्थिक/ताणिज्य/विज्ञान/प्रमुख समाचार

प्रमुख समाचार

मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार

मुंबई। वैश्विक बाजारों से मिले-जुले संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार मंगलवार 27 अक्टूबर को भारी उतार-चढ़ाव के बाद बिल्कुल सपाट बंद हुए। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों पर आने वाले फैसले को लेकर निवेशकों ने आज बेहद सावधानी बरती। बाजार में दिनभर खरीदारों और बिकवालों के बीच रस्साकशी चलती रही, जिसके चलते प्रमुख सूचकांकों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। कारोबार के अंत में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 इंडेक्स महज 3.45 अंक (0.02%) की गिरावट के साथ 22,749.75 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं, बाॅम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 8.08 अंक (0.01%) फिसलकर 73,598.67 पर बंद हुआ। हालांकि, बड़े शेयरों के मुकाबले छोटे और मझोले शेयरों में अच्छी रौनक देखी गई और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 2.69% की जोरदार बढ़त के साथ बंद हुआ।

सनटेक रियल्टी का दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 17% बढ़ा

नई दिल्ली। सनटेक रियल्टी लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 17 प्रतिशत बढ़कर 57.11 करोड़ रुपए रहा। कंपनी का शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी (जुलाई-सितंबर) तिमाही में 48.96 करोड़ रुपए था। रियल एस्टेट कंपनी ने सोमवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 की जुलाई-सितंबर तिमाही में कंपनी की कुल आय 27 प्रतिशत बढ़कर 333.82 करोड़ रुपए हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 262.16 करोड़ रुपए थी। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में कंपनी का शुद्ध लाभ बढ़कर 99.07 करोड़ रुपए हो गया, जो एक साल पहले की समान अवधि में 82.39 करोड़ रुपए था। अप्रैल-सितंबर अवधि में कंपनी की कुल आय बढ़कर 535.85 करोड़ रुपए हो गई।

टाटा मोटर्स की इवेको अधिग्रहण पेशकश को स्वीकृति

नई दिल्ली। टाटा मोटर्स की इतालवी वाणिज्यिक वाहन विनिर्माता कंपनी इवेको ग्रुप के अधिग्रहण के लिए पेशकश एक अहम पड़ाव पार कर गई है। अस्थायी नतीजों के अनुसार, कंपनी के पास मौजूद शेयर को छोड़कर पेशकशकर्ता के पास कंपनी की 89.42 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी, जो संशोधित 80 प्रतिशत की न्यूनतम सीमा से अधिक है। शेयर बाजार को दी सूचना के अनुसार, 26 अक्टूबर को समाप्त हुई पेशकश अवधि के दौरान इवेको ग्रुप के 23.816 करोड़ साधारण शेयर की पेशकश की गई, जो इवेको की कुल साधारण शेयर पूंजी का करीब 87.81 प्रतिशत हैं। यह अधिग्रहण 2008 में फोर्ड से जगुआर लैंड रोवर को खरीदने के बाद टाटा मोटर्स का सबसे बड़ा अधिग्रहण होगा। टाटा मोटर्स ने शुरुआत में इवेको के लिए प्रति शेयर 14.10 यूरो की पेशकश की थी। बाद में नौ अक्टूबर को उसने कीमत 0.30 यूरो बढ़ाकर प्रति शेयर 14.40 यूरो कर दी।

नवंबर में बदलेंगे ये 4 बड़े नियम

नई दिल्ली। नवंबर का महीना शुरू होने से पहले ही बैंकिंग, टैक्स और पेंशन से जुड़े जरूरी कामों की तैयारी कर लें। 1 नवंबर 2026 से जुड़े कई अहम अपडेट पर लोगों की नजर रहेगी। इनमें पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की समयसीमा, ऑडिट वाले करारताओं के लिए आईटीआर की अंतिम तारीख और एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संभावित बदलाव शामिल हैं। इसके अलावा, फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों पर भी नजर रखना जरूरी होगा। सरकारी पेंशन पाने वाले ज्यादातर पेंशनरों को हर साल नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। साल 2026 में सामान्य पेंशनरों के लिए यह अवधि 1 नवंबर से 30 नवंबर तक है। वहीं, 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनर 1 अक्टूबर से ही यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

में लगभग 40 प्रतिशत अधिक हैं।

कोर मुद्रास्फीति बढ़कर 4.6 प्रतिशत हो गई है, जिससे खाद्य पदार्थों, ईंधन, सेवाओं और वस्तुओं की कीमतें प्रभावित हो रही हैं। मुद्रास्फीति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए केवल मौद्रिक नीति ही पर्याप्त नहीं, इसके लिए तरलता प्रबंधन, करों के समायोजन और कृषि व आपूर्ति श्रृंखलाओं में सुधार सहित समन्वित राजकोषीय उपायों की भी आवश्यकता है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर में 25 आधार अंकों की वृद्धि कर इसे 5.50 प्रतिशत कर दिया है। यह लगभग 4 वर्षों में पहली ब्याज दर वृद्धि है। 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' से 'न्यूट्रल' की ओर रख यह दर्शाता है कि निकट भविष्य में दरों में कटौती की संभावना कम है। पश्चिम एशिया के संघर्ष और कमजोर मानसून के कारण बढ़ती खाद्य कीमतों ने मुद्रास्फीति की चिंताओं को बढ़ा दिया है। परिणामस्वरूप, अगले एक वर्ष में 100 से



अधिक आधार अंकों की अतिरिक्त दर वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। सितम्बर में, थोक मुद्रास्फीति अगस्त के 9.92 प्रतिशत से बढ़कर 11.39 प्रतिशत हो गई, जो मुख्य रूप से तेल की कीमतों में 57.32 प्रतिशत की वृद्धि से प्रेरित थी। आर.बी.आई. प्रमुख संजय मल्होत्रा ने कहा कि भविष्य में दरों में बढ़ौतरी आर्थिक वृद्धि और मुद्रास्फीति के रूझानों पर निर्भर करेगी। एक प्रमुख सवाल यह बना हुआ है कि सितम्बर में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा स्वीकार की गई कीमतों में बढ़ौतरी का कितना असर उपभोक्ता कीमतों और बिजली के बिलों पर पड़ेगा। त्र्यौहारी सीजन के दौरान आर्थिक चुनौतियां बिक्री पर निर्भर छोटे व्यवसायों को प्रभावित कर सकती हैं। बढ़ती कीमतें लाभ मार्जिन को कम कर सकती हैं लेकिन वे

हस्तनिर्मित वस्तुओं के मूल्य को भी रेखांकित करती हैं। अनूटे और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की पेशकश करके स्थानीय विक्रेता प्रामाणिकता चाहने वाले उपभोक्ताओं को आकर्षित कर सकते हैं। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की समस्याओं और घरेलू नीतियों ने भारत में मुद्रास्फीति को काफी प्रभावित किया है। सितम्बर 2023 में, भारतीय रिजर्व बैंक ने 6.2 प्रतिशत की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.) मुद्रास्फीति दर दर्ज की, जो उसके 2-6 प्रतिशत के लक्ष्य दायरे से अधिक थी। यह वृद्धि मुख्य रूप से खाद्य, ईंधन और आवश्यक वस्तुओं की ऊंची कीमतों के कारण हुई, जिसमें खाद्य मुद्रास्फीति लगभग 7.8 प्रतिशत थी। हालिया पहलों में रसोई गैस और अनाज जैसी आवश्यक वस्तुओं पर कर कटौती और सबसिडी शामिल रही है। त्र्यौहारी सीजन से पहले स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित

करने के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) ने खरीद प्रयासों को तेज कर रखा है। भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने 2026-27 के लिए 7.1 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया है, जिसमें खुरदरा मुद्रास्फीति 5.2 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। हालांकि, अक्टूबर से दिसम्बर तक वर्ष की अंतिम तिमाही में मुद्रास्फीति बढ़कर 6 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। आर.बी.आई. प्रमुख ने इस बात पर जोर दिया कि अर्थव्यवस्था मजबूत होने के बावजूद बढ़ती मुद्रास्फीति चिंता का विषय बनी हुई है। खुरदरा विक्रेता बंडलड डील्स और आवश्यक वस्तुओं पर छूट के माध्यम से पैसे के सही मूल्य (वैक्यू फॉर मनी) पर जोर देकर इन आर्थिक रूझानों के अनुकूल ढल रहे हैं। इस दृष्टिकोण ने मध्यम श्रेणी के उत्पादों की बिक्री में 15 प्रतिशत की वृद्धि की है, जबकि विलासिता की वस्तुओं की मांग में गिरावट आई है।

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न संवर्गों में नवनियुक्त 520 कर्मचारियों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र

रोगियों की सेवा को पुण्य कार्य मानकर पूरी निष्ठा व संवेदनशीलता से निभाएं अपना दायित्व : साय

रायपुर। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और प्रत्येक नागरिक तक बेहतर उपचार की पहुंच सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। स्वस्थ नागरिक ही सशक्त समाज और विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव हैं। हमारी सरकार का प्रयास है कि शहरों के साथ-साथ गांवों, जनजातीय अंचलों और दूरस्थ क्षेत्रों में भी लोगों को समय पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर के सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न संवर्गों में नवनियुक्त 520 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी नवनियुक्त कर्मचारियों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए सेवाभाव, संवेदनशीलता और पूरी निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया।



‘मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में सेवा का अवसर मिलना अपने आप में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अस्पताल आने वाला प्रत्येक व्यक्ति और उसका परिवार स्वास्थ्यकर्मियों की ओर बड़ी आशा और विश्वास से देखता है। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े प्रत्येक कर्मचारी की जिम्मेदारी केवल अपने शासकीय दायित्वों के निर्वहन तक सीमित नहीं है, बल्कि मरीजों के प्रति संवेदनशील व्यवहार और सेवाभाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त कर्मचारियों से कहा कि रोगियों की सेवा से बढ़कर कोई कार्य नहीं है। आप अपनी ड्यूटी को केवल नौकरी न मानें, बल्कि जनसेवा और पुण्य का कार्य समझकर पूरी ईमानदारी, मनोयोग और समर्पण से कार्य करें। आपके अच्छे व्यवहार, तत्परता और सेवाभाव से मरीजों और उनके परिजनों का स्वास्थ्य

व्यवस्था के प्रति विश्वास और मजबूत होगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अच्छा स्वास्थ्य जीवन में आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने की पहली आवश्यकता है। स्वस्थ छत्तीसगढ़ से ही विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण संभव है। जब हमारे नागरिक स्वस्थ होंगे, तभी वे अपनी पूरी क्षमता के साथ परिवार, समाज और प्रदेश की प्रगति में योगदान दे सकेंगे। इसी सोच के साथ राज्य सरकार स्वास्थ्य अधीनसंरचना के विस्तार के साथ मानव संसाधन की उपलब्धता बढ़ाने पर भी लगातार कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद बीते 25 वर्षों में स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। राज्य सरकार इस यात्रा को और गति देते हुए नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के विकास, आवश्यक उपकरणों और संसाधनों की उपलब्धता तथा स्वास्थ्य अमले को मजबूत करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। हमारा लक्ष्य ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था विकसित करना है।

निलंबित लाइसेंस पर वाहन चलाने वालों पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई : एसएसपी सिंह



सड़क सुरक्षा पर सख्ती, 10 माह में 892 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित

बिलासपुर। कलेक्टर संजय अग्रवाल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह की अध्यक्षता में आज जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और सुरक्षित एवं सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि यातायात नियमों के उल्लंघन पर जनवरी से अक्टूबर माह तक 892 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। एसएसपी श्री रजनेश सिंह ने

स्पष्ट किया कि निलंबित लाइसेंस के बावजूद वाहन चलाते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सड़क सुरक्षा की दिशा में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई। बताया गया कि सड़क चौड़ीकरण का कार्य कराया गया है। इससे मोड़ पर दुर्घ्यता बेहतर होने के साथ वाहनों का आवागमन अधिक सुरक्षित एवं सुगम होगा। इसी प्रकार लगार मोड़ एवं ग्राम जांजी में भी शीघ्र मरम्मत कार्य शुरू किया जाएगा। इन कार्यों

से यातायात व्यवस्था में सुधार के साथ सड़क दुर्घटनाओं की आशंका कम करने में मदद मिलेगी। एसएसपी रजनेश सिंह ने यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में विशेष अभियान चलाने को कहा। उन्होंने विद्यार्थियों को यातायात नियमों और सुरक्षित आवागमन के संबंध में जागरूक करने पर जोर दिया। बैठक में नगर निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे, जिला पंचायत सीईओसंदीप अग्रवाल, अपर कलेक्टर, आरटीओ सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए मतदान केंद्रों का निरीक्षण



रायपुर। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में दिनांक 23 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया है। प्रकाशित मतदाता सूची के संबंध में मतदान केंद्रों पर

दावा-आपत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक श्रीमती सीमा ठाकुर, अपर कलेक्टर द्वारा विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर दावा-

आपत्ति प्राप्ति की प्रक्रिया का अवलोकन किया गया। इस दौरान मतदाता सूची की शुद्धता एवं त्रुटिरहित निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया।



रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा महिलाओं से जुड़े प्रकरणों की सुनवाई के लिए 28 एवं 29 अक्टूबर को रायपुर में जनसुनवाई आयोजित की जाएगी। आयोग की अध्यक्ष श्रीमती ममता साहू के नेतृत्व में आयोग के अन्य सदस्य भी सुनवाई में शामिल होंगे। जनसुनवाई का उद्देश्य पीड़ित महिलाओं को अपनी समस्याएं आयोग के समक्ष रखने का अवसर देना और उन्हें त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में पहल करना है।

न्यायधानी नाइट्स और चक्रधर चौपियंस के बीच कड़ा मुकाबला 4-4 से ड्रॉ

रायपुर। छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के एक और तेज-तर्रार मुकाबले में आज एस.वी. सुनील की 'चक्रधर चौपियंस' और सुरेंद्र सिंह की शन्यायधानी नाइट्स के बीच मैच 4-4 से ड्रॉ रहा। चौपियंस के लिए युवराज वाल्मीकि तीन गोल करके हीरो बने, जबकि नाइट्स की ओर से केतन ने बेहतरीन हॉकी का प्रदर्शन किया। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग की निदेशक प्रो. रीता वेणुगोपाल, जिल्दल रूप के उपाध्यक्ष श्री यू.पी. सिंह, अडानी रूफ के वरिष्ठ प्रबंधक श्री अतुल कुमार गुप्ता और छत्तीसगढ़ हेतुकी संघ के सचिव श्री सही राम जाखड़ भी इस मैच को देखने स्टेडियम पहुंचे थे। उन्होंने ने में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए।



बिलासपुर नाइट्स की संतुलित टीम किसी एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं है। जहाँ चिराग पेनल्टी कॉर्नर के विशेषज्ञ हैं, वहीं केतन, आदर्श और सोनू निषाद ने फॉरवर्ड लाइन में शानदार खेल दिखाया है। जब चिराग छह पेनल्टी कॉर्नर

को गोल में बदलने से चूक गए, तब टीम के अन्य खिलाड़ियों ने जिम्मेदारी संभाली। वहीं चक्रधर चौपियंस की टीम में एस.वी. सुनील और वाल्मीकि मुख्य रूप से टीम का भार उठाते रहे हैं। इस मैच में दोनों टीमों की इन अलग-अलग खूबियों को देखने का मौका मिला। मैच के दूसरे क्वार्टर में केतन और आदर्श ने शन्यायधानी के लिए स्कोरिंग की शुरुआत की। केतन ने दाईं ओर से दौड़ते हुए चार डिफेंडरों को छकाया और बहुत आसानी से सकल को अंदर प्रवेश किया। उन्होंने आखिरी पल में आदर्श को पास दिया, जिन्होंने गेंद को गोल में पहुंचा दिया। दूसरा गोल आने में ज्यादा समय नहीं लगा। इस बार केतन बाईं ओर से सकल में दाखिल हुए और सोनू निषाद ने गेंद को डिफ्लेक्ट (दिशा बदलकर) करके गोल कर दिया, जिससे हाफ-टाइम तक उनकी टीम 2-1 से आगे हो गई।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

श्री गीता ज्ञान अमृत वर्षा कथा 29 तक

रायपुर। कार्तिक माह के पावन अवसर पर राजधानी रायपुर में धर्म, अध्यात्म, ज्ञान और भक्ति की दिव्य धारा प्रवाहित होने जा रही है। श्रीमद्भगवद्गीता के शाश्वत संदेश को जन-जन तक पहुंचाने तथा जीवन में ज्ञान, भक्ति और कर्म के महत्व को उजागर करने के उद्देश्य से तीन दिवसीय श्री गीता ज्ञान अमृत वर्षा कथा' का आयोजन 27 अक्टूबर तक किया गया है। कथा के समापन के अगले दिन, 30 अक्टूबर को सुबह 7 बजे हवन पूजन होगा। यह आध्यात्मिक आयोजन रायपुर के अश्वनी नगर स्थित सोनकर मैरिज पैलेस में किया गया है। आयोजनकर्ता श्रीमती नमिता पात्रा एवं मां कामाख्या धर्मांध ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने धार्मिक आयोजन में सहभागी बनने का अनुरोध किया है। प्रयागराज से पधारे परम पूज्य गुरुदेव श्री संकर्षण शरण जी (गुरुजी) अपने श्रीमुख से श्रद्धालुओं को श्रीमद्भगवद्गीता के दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक चिंतन और जीवनीपयोगी संदेशों से परिचित कराएंगे। कथा के माध्यम से भगवान श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए कर्म, धर्म, भक्ति और कर्तव्य के उपदेशों को सरल एवं सहज रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि श्रद्धालु गीता के संदेशों को अपने दैनिक जीवन में आत्मसात कर सकें।

भाजपा सरकार बनने के बाद सरकारी नौकरी की भर्ती बंद : कांग्रेस

रायपुर। रिक्त सरकारी पदों पर नियमित भर्ती प्रक्रिया को बाधित करने का आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा है कि भाजपा ने 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी की गारंटी के तहत 100 दिनों के भीतर अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण और युवाओं के लिए नियमित पदों पर 1 लाख सरकारी भर्तियों का वादा किया था। हकीकत यह है कि नई भर्तियों पर ब्रेक लगा दिया गया है, शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती, वन विभाग और न्यायिक सेवा में नियुक्ति बाधित है, पीएससी भर्ती परीक्षाओं का भी हाल सर्वविदित है और पुरानी प्रक्रियाओं को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने राज्य के युवाओं और लाखों अनियमित कर्मचारियों के साथ ऐतिहासिक विश्वासघात किया है। मोदी की गारंटी का ढोल पीटकर सत्ता में आई साय सरकार ने 100 दिनों के भीतर नियमितीकरण का वादा किया था, लेकिन आज युवा और अनियमित कर्मचारी सड़कों पर गुहार लगाने को मजबूर हैं। भर्तियों को रोककर और युवाओं का भविष्य अंधकार में धकेलकर भाजपा सरकार ने यह साबित कर दिया है कि उनके वादे सिर्फ वोट बटोरने का जुमला थे।

सामाजिक विकृति के लिए अभिभावक जिम्मेदार पक्ष-विपक्ष ने दृढ़ता से रखे विचार

रायपुर। अंकित कुमार राठौर ने कहा कि आज अभिभावकों का लाड़-प्यार और डिजिटल लापरवाही बच्चों को सामाजिक विकृति की ओर ले जा रही है। पैरेंट्स बच्चों को समय से पहले मोबाइल न दें, तो बच्चे को लत लगेगी ही नहीं। अभिभावक ही बच्चों को अनुशासन नहीं सिखा पा रहे हैं। वहीं विपक्ष के उमेश मेथ्राम ने कहा कि एक ही घर में अच्छे और बुरे, दोनों सदस्य होते हैं। दो भाइयों में अलग-अलग संस्कार परिलक्षित होते हैं, तो क्या आप यह कहेंगे कि दोनों को अलग-अलग संस्कार दिए गए। यह तो हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उन संस्कार को कैसे ग्रहण करते हैं। बात हो रही है मराठी सोहळा (मेला) के तीसरे और अंतिम दिन की, जिसमें महाविद्यालय स्तरीय वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विषय था सामाजिक विकृति के लिए अभिभावक जिम्मेदार। जिस पर पक्ष और विपक्ष, दोनों ने पूरी दृढ़ता के साथ अपने-अपने विचार रखे। सामाजिक विकृति के लिए अभिभावक को जिम्मेदार मनाते हुए पक्ष में अपने विचार रखते हुए सभी में मैक कालेज की हर्षिता परिदा ने प्रथम स्थान और धवल शाह ने दूसरा स्थान प्राप्त किया।

दिवाली पर किसानों की खुशियां छीनने पर तुली है सरकार : कांग्रेस

रायपुर। भाजपा सरकार पर किसानों से वादाखिलाफी और षडयंत्रकारी नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का अन्नदाता गहरी पीड़ा और संकट के दौर से गुजर रहा है। जिस धान और किसानों के बूते छत्तीसगढ़ की संस्कृति और अर्थव्यवस्था धड़कती है, उसी अन्नदाता के साथ भाजपा सरकार क्रूर मजाक कर रही है। सिर पर दीपावली का त्योहार है, लेकिन किसानों के घरों में अंधेरा है। सरकार ने चुनाव से पहले बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन आज हकीकत यह है कि किसान रकबा कटौती के षडयंत्र, टोकन और तौल की धांधली का शिकार हो रहा है। हम मांग करते हैं कि सरकार तत्काल 3358 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ का एकमुश्त भुगतान और दिवाली से पहले एडवांस सुनिश्चित करे, अन्यथा कांग्रेस पार्टी राज्यभर के किसानों के साथ सड़क से सदन तक आर-पार की लड़ाई लड़ेगी। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि डबल इंजन सरकार की दुर्भावना से छत्तीसगढ़ का अन्नदाता इस समय भारी आर्थिक संकट और मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहा है। दिवाली जैसा बड़ा त्योहार फिर पर है, लेकिन किसानों के पास जेब में फूटी कौड़ी नहीं है।

कलेक्टर-एसएसपी ने जनदर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं



बिलासपुर। कलेक्टर संजय अग्रवाल एवं एसएसपी रजनेश सिंह ने आज जिला कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनीं। जनदर्शन में लोगों ने निजी एवं सामुदायिक समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत कर निराकरण की मांग की। कलेक्टर एवं एसएसपी ने आवेदकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और अधिकांश मामलों में मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान नगर निगम कमिश्नर श्री प्रकाश कुमार सर्वे ने भी लोगों की समस्याएं सुनीं। जनदर्शन में ग्राम पंचायत निरतू के सरपंच ने कलेक्टर को जापन सौंपकर बताया कि ग्राम पंचायत निरतू एवं उसके आश्रित ग्राम अदराली में जल जीवन मिशन के तहत निर्मित पानी टंकी से अब तक पेयजल वितरण शुरू नहीं हुआ है। पानी टंकी बनने के बावजूद ग्रामीणों को नियमित पेयजल सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था के साथ माता मावली की डोली और दंतेश्वरी माई के छत्र को दी विदाई

बस्तर दशहरा का हुआ समापन, कलश यात्रा के साथ माता मावली को दी गई विदाई

जगदलपुर। ऐतिहासिक बस्तर दशहरा के 75 दिवसीय विशाल धार्मिक अनुष्ठानों का विधिवत समापन मंगलवार को माता मावली की डोली और मां दंतेश्वरी के छत्र की ससम्मान विदाई के साथ हुआ। बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर के राजमहल परिसर स्थित ऐतिहासिक मां दंतेश्वरी मंदिर में परंपरागत विधि-विधान और मंत्रोच्चार के साथ विशेष पूजा-अर्चना संपन्न की गई। इसके उपरांत पुलिस के जवानों ने माता को सलामी दी। विदाई के इस पावन और भावुक क्षण में सिर पर कलश धारण किए महिलाओं ने मंगल गीतों के साथ माता को अत्यंत आत्मीय विदाई दी, जिससे संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो उठा।

माता की इस ऐतिहासिक विदाई यात्रा के लिए दंतेश्वरी मंदिर परिसर और विदाई मार्ग को लगभग डेढ़ क्विंटल गेंदे, गुलाब और बासंती फूलों की सुंदर पंखुड़ियों से सजाया गया था। डोली के प्रस्थान के समय उपस्थित जनसमुदाय और श्रद्धालुओं ने जयकारों के बीच माता पर गुलाब की पंखुड़ियों की पुष्पवर्षा कर आस्था के साथ विदा किया। इस धार्मिक विधान में बेल और



सागौन की लकड़ी से निर्मित करीब 15 साल पुरानी डोली आकर्षण का मुख्य केंद्र रही, जिसमें करीब चार किलो चांदी, दोनों ओर चांदी की प्रतिमाएं और 45 चांदी के गुब्बे जड़े हुए हैं।

परंपरा अनुसार बस्तर राजपरिवार के सदस्य श्री कमलचंद्र भंडेवर और श्रद्धालुओं को माता की करीब 20 किलो वजनी डोली को कंधों पर उठाकर जिया डेरा तक पहुंचाया, जिसके बाद डोली और छत्र को दत्तेवाड़ा के लिए विदा किया गया। इस पावन अवसर पर मंदिर पहुंचे दर्शनार्थियों को 76 किलो बूंदी और लड्डू से तैयार किए गए 5 हजार से अधिक पैकेटों में प्रसाद का वितरण किया गया। साथ ही माता को विदाई रस्म के तहत 25 किलो चावल, 11 किलो दाल, घी, मसाले और श्रृंगार सामग्री भेंट स्वरूप अर्पित की गई। ऐतिहासिक बस्तर दशहरा के 75 दिवसीय विशाल धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान अनेक देवी-देवताओं की उपस्थिति में संपन्न हुए उक्त आयोजन के साथ ही बस्तर के इस अनूठे पारंपरिक पर्व का औपचारिक समापन हो गया।

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि 1 नवंबर को दिल्ली में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की “वोट बचाओ, देश बचाओ” रैली रामलीला मैदान में आयोजित है। इस रैली में छत्तीसगढ़ से भी बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ से सभी जिलों के कार्यकर्ता टेन्जो बसो एवं वायु मार्ग तथा निजी वाहनों में दिल्ली रवाना होंगे। समूचे देश से 10 लाख से अधिक लोग मोदी और ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा लेने दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ का हर नेता कार्यकर्ता, पदाधिकारी दिल्ली आवश्यक रूप से पहुंचेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तथा एसआईआर

के निरस्तीकरण और काटे गये वोटों की बहाली तक कांग्रेस का आंदोलन चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि देश में हुए वोट चोरी के लिये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जवाबदार है। ज्ञानेश कुमार ने मोदी के प्रभाव में आकर तथा मोदी और शाह के संरक्षण में वोट चोरी

जैसे अलोकतांत्रिक काम की अंजाम दिया है। भाजपा ने फर्जी राष्ट्रवाद का राग अलाप कर और घुसपैठिये का भय दिखाकर देश से मतदाताओं का सेलेक्टिव रूप से मतदाता सूची से नाम कटवाया। एसआईआर मतदाता सूची का शुद्धिकरण नहीं गैर भाजपाई मतदाताओं का नाम काटने का अभियान था। ऐप के माध्यम से प्रिंटर लगाकर टारगेटेड वोट, असंवैधानिक तरीके से काटे गये। पूरे देश में 13 करोड़ मतदाताओं का नाम काटा जाना सामान्य बात नहीं है। एसआईआर से घबरा कर देश के सैकड़ों लोगों ने आत्महत्या किया, जब-जब यह साबित हो गया कि देश में वोट चोरी हुई है तो दोषियो को सजा मिलनी ही चाहिये।